



महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सचिन पायलट शामिल हुए।

इस बार तेरे या मेरे नाम पर टिकट नहीं मिलेगा-पायलट

पायलट ने यह भी कहा कि, सरकार कार्यकर्ताओं के दम पर बनती है

जयपुर, 2 अक्टूबर (का.प्र.)। राजस्थान विधानसभा के लिए टिकट देने के लिए प्रत्याशियों के चयन पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। इस मुद्दे पर सोमवार को सचिन पायलट ने, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर गांधी और शास्त्री जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, राजस्थान में प्रत्याशी के लिए केवल चुनाव जीतना ही एकमात्र क्राइटेरिया तय किया गया है। जब फाइनल लिस्ट आरंभ तो पहले से ज्यादा युवाओं, एससी-एसटी, ओबीसी माइनोंरिटी सबको प्राथमिकता देगे, लेकिन जितना को इनोवर नहीं कर सकते हैं। पायलट ने कहा कि, इस बार "ये तेरा या मेरा" के नाम पर टिकट नहीं मिलेगा। पायलट ने स्पष्ट किया कि, कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से गंभीर है कि कैसे जितना उम्मीदवार को टिकट दिया जाए।

सचिन पायलट ने यह भी कहा कि, सरकार कार्यकर्ताओं के दम पर बनती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता उल्लासित है वह जानता है कि, भविष्य हमारा है। नौजवानों, किसानों और कार्यकर्ताओं के मन में जो अभिलाषा है वह तभी पूरी होगी जब कांग्रेस की सरकार रिपोर्ट होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पार्टी के कार्यकर्ता बनाती है, पार्टी के कार्यकर्ता व नेता के दम पर हम जनता तक सरकार को बात पहुंचाते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं और राजस्थान में सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, तभी जनता भी विश्वास कर रही है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है, पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ रही है, जहां कहीं भी हमें छोटा-मोटा

सीटों के बंटवारे पर मतभेद

जालिगत जनगणना के आंकड़ों की घोषणा ने बिहार में जनता दल युनाइटेड एवं राष्ट्रीय जनता दल के सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी भाजपा के बीच तगड़ा वाक्युद्ध छेड़ दिया है। जद, यू नेता एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उसकी सहयोगी आर.जे.डी. के पितृपुरुष लालू प्रसाद यादव ने इस रिपोर्ट के प्रकाशन को जहां ऐतिहासिक

इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे में और देरी हो सकती है, क्योंकि जिन सीटों पर सभी दल प्रत्याशी खड़े करना चाहते हैं, उन्हें लेकर विवाद बढ़ रहा है।

शेयरिंग में मुश्किलें आ सकती हैं। उन सीटों पर विवाद बढ़ रहा है जिन पर सभी पार्टियां दावा कर रही हैं। गत 13 सितंबर को शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर हुई पिछली कोआर्डिनेशन मीटिंग में चार मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन उनमें से अब तक एक ही मुद्दे पर अमल किया गया है। कांग्रेस तथा कुछ

महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया के साथ बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि, चुनाव जीतना ही एक मात्र क्राइटेरिया है तथा एस.सी./एस.टी. ओ.बी.सी. व माइनोंरिटी को पहले से ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

पायलट ने राजस्थान में गठबंधन से इंकार किया व कहा कि, इंडिया एलायंस राष्ट्रीय स्तर पर है, राजस्थान में सिर्फ दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा।

कास्ट सर्वे रिपोर्ट पर नौ दलों की बैठक आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी

पटना, 2 अक्टूबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आज प्रकाशित कर दी गई और मंगलवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे नौ दलों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सबकी राय लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कुमार ने सोमवार को यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी संग्रहालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है। नौ पार्टियों की सहमति से यह सब हुआ है। उन सब पार्टियों के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने कहा

नीतीश ने कहा कि सभी दलों से राय लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कहा कि, सबको लाभ मिले इसको लेकर कल की बैठक में एक-एक चीज को रखा जायेगा। कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अतिपिछड़ी जातियों के लिए विश्वकर्मा योजना लागू किये जाने और बिहार में अतिपिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ने के सवाल पर कहा कि, उन्हें यह सब पता नहीं है कि उन लोगों ने क्या लागू किया है। बिहार में हम लोगों ने जितना काम किया है उतना आज तक कोई नहीं किया है। बिहार में किसी एक जाति नहीं बल्कि सभी जातियों के हित में काम आगे बढ़ेगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने जनगणना कराई थी लेकिन इसके 10 वर्षों के बाद जनगणना नहीं हुई है।

की वकालत की है। उन्होंने कहा कि, इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन राजस्थान में हमेशा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है क्योंकि अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। पार्टी छोड़कर गए नेताओं को लेकर पायलट ने कहा कि, चुनाव के समय कुछ लोग पार्टी छोड़ेंगे कुछ जाइन भी करेंगे। यह निर्णय निर्णय होता है। यह सही है या गलत, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और जीतने की स्थिति में है।

नवरात्रि में घोषित होगी राजस्थान में भाजपा की पहली लिस्ट

जाल खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में केन्द्रीय निर्वाचन समिति ने रविवार को राजस्थान विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की

प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को प्र. मंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसमें वसुंधरा राजे, राजेन्द्र राठौड़, सतीश पुनिया आदि के नाम होने की संभावना है।

पहली और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए इसकी सूची को स्वीकृति दे दी लेकिन नामों की घोषणा 15 अक्टूबर से आरंभ होने वाले नवरात्रों में की जाएगी। 30 से ज्यादा नामों को स्वीकृति दी गई है जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विपक्ष के नेता राजेन्द्र सिंह राठौड़, पूर्व भाजपाध्यक्ष सतीश पुनिया तथा सांसद दिया कुमारी गुर्जर, सुखबिर सिंह जौनपुरिया, किरोड़ी लाल मीणा तथा

बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ से अधिक है, इसमें से 36 प्रतिशत अति पिछड़ी जातियां व 27.13 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियां हैं।

जद (यू) व राष्ट्रीय जनता दल ने कास्ट सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने को एतिहासिक मौका बताया, वहीं भाजपा की बिहार इकाई ने इसे ढकोसला की संज्ञा दी है।

लेकिन, भाजपा की प्रदेश इकाई कास्ट सर्वे रिपोर्ट का श्रेय लेने की कोशिश में अवश्य जुट गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि, कास्ट सर्वे को हमारा पूर्ण समर्थन था, हमने ही इसे शुरू करवाया था।

डिज़ाइन बॉक्स के अरोड़ा की भारी तरफदारी की भंवर जीतेन्द्र सिंह ने

डोटासरा को जीतेन्द्र सिंह ने सलाह दी कि, लड़ाई छोड़ कर डिज़ाइन बॉक्स राजस्थान में और काम दें

रेणु मित्तल-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। ऐसी खबर है कि गांधी परिवार के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रखने वाले कांग्रेस के एक सोनियर नेता ने राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा को फोन कर कहा है कि वह डिज़ाइन बॉक्स के मुखिया अरोड़ा के साथ हुई तकरार को भूल जाएं। उन्होंने डोटासरा से यह भी कहा कि वह अरोड़ा को और काम दें।

अलवर के नेता जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देने के बावजूद भी अरोड़ा की पैरवी करना जारी रखा कि डिज़ाइन बॉक्स के प्रमुख ने राहुल गांधी के लिए अपशब्द कहे थे और वह तो यहां तक कह गए थे कि राहुल नेता बनने लायक नहीं हैं और यदि पार्टी उनकी बात सुने या उनके कहने पर चले तो वह जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते।

डोटासरा दुविधा में हैं, क्योंकि अरोड़ा ने राहुल गांधी के बारे में बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है और यह भी कहा है कि, वे नेता बनने लायक नहीं हैं।

जीतेन्द्र सिंह ने असम के प्रभारी के रूप में, डिज़ाइन बॉक्स को कांग्रेस का चुनाव अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर पार्टी की भारी हार हुई थी।

दो अन्य प्रमुख नेता, हिमाचल की आशा कुमारी और उनके भाई, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी डिज़ाइन बॉक्स के समर्थक बताये जाते हैं।

जीतेन्द्र सिंह की सलाह पर ही राजस्थान में डिज़ाइन बॉक्स को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी दी गयी है।

सूत्र बताते हैं कि जितेन्द्र सिंह जब असम के ए.आई.सी.सी. प्रभारी थे, तब उन्होंने असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए इसी डिज़ाइन बॉक्स को हायर किया था, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह

पराजित हुई थी। यह पहले ही बताया जा चुका है कि जितेन्द्र सिंह ने ही अशोक गहलोत को डिज़ाइन बॉक्स को हायर करने की सलाह दी थी। जितेन्द्र सिंह के अलावा कांग्रेस के दो अन्य सोनियर नेताओं, हिमाचल

प्रदेश की आशा कुमारी और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं उनके भाई टी.एस. सिंह देव ने डिज़ाइन बॉक्स की पैरवी करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यद्यपि डिज़ाइन बॉक्स अपने काम से कांग्रेस को किसी भी राज्य में नहीं जितवा सका। क्या इन नेताओं के डिज़ाइन बॉक्स के साथ कोई बिजनैस लिंक्स हैं? यह बात अभी भी जांच का विषय है।

सूत्र कहते हैं कि घटना और तकरार को भूल जाने की जितेन्द्र सिंह द्वारा सलाह दिए जाने के बाद आवेशित डोटासरा मीडिया में चले गए और उन्होंने एक हिंदी दैनिक को अपना साक्षात्कार दिया। राजस्थान और कांग्रेस हलकों में अब यह प्रश्न किया जा रहा है कि अरोड़ा एक ऐसी पार्टी को कैसे जीत दिला सकते हैं, जहां वह स्वयं ही उसके सोनियर नेताओं को अपशब्द कह

राज्य के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने कहा है कि, सरकार 2015 के सामाजिक आर्थिक सर्वे (जात आधारित जनगणना) की रिपोर्ट स्वीकार करने पर विचार कर रही है।

पर ऐसी आशंका है कि, इस रिपोर्ट के जारी होने से वोक्लिग व लिंगायत समुदाय नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जात आधारित जनगणना के आंकड़ों से इन समुदायों की सही संख्या पता लग सकती है।

जनगणना की रिपोर्ट जारी न करने के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। यह कदम भाजपा के हिन्दुत्व के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए उठाया गया है। अब राहुल गांधी ने यह मांग की है और पहले बिहार के नेताओं नीतीश कुमार और लालू यादव ने यह मांग की थी और बाद में अन्य विपक्षी दलों ने भी मुद्दा उठाया। उम्मीद है कि इससे सबसे

अमृतसर, 2 अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को निजी दौर पर अमृतसर पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। गांधी ने सिर पर पगड़ी की जगह नीले रंग का पटका बांधा हुआ था। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद लंगर हॉल में बर्तन सेवा की। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार गांधी का अमृतसर का यह निजी दौरा है। उनका पंजाब में पार्टी

सिर पर नीला पटका बांधे राहुल ने लंगर हॉल में बर्तन सेवा भी की।

नेताओं से मिलने या कोई जनसभा करने का कार्यक्रम नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों विशेषकर सुखपाल सिंह खेरा की राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा की गयी गिरफ्तारी के सम्बंध में राहुल से मिलना चाहते हैं। पार्टी नेता राहुल को उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के बारे में भी बताना चाहते हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें जेलों में डाला है। इससे पहले राहुल गांधी का यहाँ अमृतसर हवाई अड्डे पर

यह जनगणना कांग्रेस की पूर्व सिद्धारमैया सरकार (2013-18) ने करवाई थी

लक्ष्मण बेंकट कुची-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के तुरंत बाद कांग्रेसनेता कर्नाटक सरकार की पूर्व में सिद्धारमैया सरकार (2023-2018) द्वारा करवाई गई जातीय जनगणना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया यह संकेत दे चुके हैं कि सरकार 2015 में करवाए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे को स्वीकार करने की सोच रही है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद कांग्रेस सरकार का भी रास्ता खुल गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओ.बी.सी. की जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है और यू.पी.ए. सरकार द्वारा करवाई गई जात आधारित

जातिगत जनगणना करवाएंगे। यादव के पुत्र एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि रिपोर्ट का प्रकाशन दर्शकों लम्बे इस संघर्ष में मील का एक पत्थर है। उन्होंने कहा कि "इस सर्वे ने न केवल जातिगत आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी हवाला दिया है। अब सरकार इस डेटा के आधार पर संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगी।"

उपमुख्यमंत्री ने भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा कि "इतिहास गवाह है कि भाजपा ने तुरंत तो किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की। बिहार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिहार ने एक रास्ता दिखाया है।" भाजपा के सोनियर नेता एवं केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को एक ढकोसला बताते हुए कहा कि "यह सर्वे लोगों में संशय उत्पन्न करने वाला है।"

राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका

विचार बिन्दु

हृदय की विशालता ही उन्नति की नींव है। —जवाहरलाल नेहरू

एक देश, एक शिक्षा

प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष, 2047 तक भारत देश के विश्व के विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित कराना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, अब तक की यात्रा विकासशील देश के रूप में रही है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि देश की पूरी जनसंख्या, देश की प्रतिभे में सक्रिय और अपना क्षमता अनुसार पूरा योगदान दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि देश के सभी बच्चों को समान रूप से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। विश्व में कोई भी ऐसा विकसित देश नहीं है जहां के सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध न हों। शिक्षा में जितनी असमानता हमारे देश में है, उतनी संभवतया किसी देश में नहीं है। सर्वाधिक समृद्ध देश अमेरिका में भी लगभग 90 प्रतिशत बच्चों को एक समान स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है एवं वे सभी बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। भारत में यह स्थिति ठीक उल्टी है। ठीक-ठाक शिक्षा भी केवल पांच प्रतिशत बच्चों को ही प्राप्त है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में आया और उसमें विद्यालयों के लिए कुछ न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए गए। यह खेद का विषय है कि आर टी ई कानून लागू होने के लगभग 13 वर्ष बाद एवं स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी भारत के लगभग 15 लाख विद्यालयों में से अधिकतम एक लाख विद्यालय ही ऐसे हैं जो आईटीआई कानून में लिखी गई विभिन्न शर्तों की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के प्रति सरकारी की उत्तरदायिता का ही परिणाम है कि न तो भात का कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में स्थान बना पाया एवं न ही यहां की स्कूलों शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी असमानता भारत में है, उतनी किसी अन्य देश में नहीं है। दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करना पाठकों के लिए उपयोगी होगा।

दृश्य एक— शहर के किसी कच्ची बरती अथवा गांव का राजकीय विद्यालय कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। पास में गंदे पानी का नाला बह रहा हो। आसपास, गाय भैंस, बकरियां आदि जानवर मुक्त रूप से विचरण करते हैं। जहां पर दो कच्चे पक्के छोटे कमरे हों। बिजली की नियमित व्यवस्था न हो। खेल के मैदान का तो प्रश्न ही नहीं। बालिकाओं के शौचालय न हों। शिक्षक इक्का-दुक्का ही वहां पर स्थापित हों और वे भी अपनी इच्छा अनुसार कभी-कभार विद्यालय आते हों। अनुपस्थित अध्यापकों के बारे में पता करने पर बताया जाए कि वे कोई सूचना देने शिक्षा अधिकारी के कार्यालय गए हैं। बच्चों के बैठने के लिए न बेंच की व्यवस्था हो न टेबल कुर्सी की। पीने का पानी नहीं हो। अधिकांश विद्यालयों में बैठने के लिए फटी हुई टाट पट्टी हो। एक-एक कमरे में दो-तीन कक्षा के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके अलग-अलग समूह में बैठा दिया गया हो, और एक ही शिक्षक सबको एक साथ पढ़ाने का उपक्रम करता हो।

इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5-7 वर्ष की तथाकथित स्कूलों शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी न तो सरल अंकगणितीय गणना कर सकते हैं, न ही सरल हिंदी में लिख-पढ़ या समझ सकते हैं। इसकी पुष्टि 'प्रथम' संस्थान द्वारा किए गए शिक्षा के स्तर के वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Status of Education Report) में 'गत कई वर्षों से हो रही है। शिक्षा की प्राथमिकता न दिए जाने का ही परिणाम है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के स्थान पर अधिकांश बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर में गिरावट हो देखा जा रहा है। देश के 90 प्रतिशत बच्चे ऐसे ही विद्यालयों में पढ़ रहे हैं।

दृश्य दो— बहुत बड़ा स्कूल परिसर है। बच्चों को स्कूल की बस या कारों के द्वारा लाया जा रहा है। हरे-भरे, लंबे-चौड़े खेल के मैदान हैं। प्रत्येक क्लासरूम वातानुकूलित है, स्मार्ट बोर्ड भी है। प्रत्येक बच्चे के पास लैपटॉप है। सुसज्जित प्रयोगशाला है। सभी बच्चे साफ-सुथरी अच्छी यूनिफॉर्म में आते हैं। प्रति दिन विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। पढ़ाई के अलावा कई गैर शैक्षणिक गतिविधियां समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। इन विद्यालयों के माता-पिता, बच्चों को घर पर पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

इस प्रकार के कुछ विद्यालय किसी ट्रस्ट या मिशनरी द्वारा संचालित हैं, किन्तु अधिकांश, व्यवसाय की तरह संचालित किए जाते हैं।

दृश्य 3— गली मोहल्ले में खास पर शहरों की कच्ची बस्तियों में आजकल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, जहां पर 1000-1500 मासिक फीस ली जाती है।

इनमें तथा-कथित रूप से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। घरों पर काम करने वाले, ड्राइवर अथवा मजदूरी करने वाले कई अभिभावकों के बच्चे इनमें पढ़ते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि निर्धन व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए वे दिन-रात कड़ी मेहनत करते, अपनी कमाई से से कुछ पैसे बचा कर, बच्चों की फीस जुटाते हैं। इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का शोषण होता है और उन्हें 5-7000/- प्रति माह का वेतन मिलता है। ऐसे विद्यालय को चलाने वालों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को व्यवसाय की तरह ही चलाना है।

दूसरी श्रेणी के विद्यालय जिनका उल्लेख ऊपर किया है, उन्हें चलाने वाले अधिकांश व्यवसायी होते हैं, जिन्होंने शराब, पत्थर, परिवहन या रियल एस्टेट जैसे व्यवसाय से अकूत सम्पत्ति अर्जित कर शिक्षा को भी व्यवसाय की तरह चलाना प्रारंभ किया है। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर मेडिकल विश्वविद्यालय तक उपलब्ध हैं। शिक्षा के निर्जीकरण का जो दौर लगभग 30 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, वह अब चरम पर है। अच्छी सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के दायित्व से सरकारों ने लगता है, मुंह मोड़ लिया है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में लगभग सारे विद्यालय सरकारी हैं। भारत में भी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि सरकार चाहे तो शिक्षा विद्यालय संचालित कर सकती है।

दृश्य एक में उल्लिखित विद्यालय अमीर, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए सीमित होकर रह गए हैं। स्वाभाविक है, जो विद्यार्थी ऐसे विद्यालय से निकलेंगे, वे जीवन की हर दुर्घटना में अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में पहले से ही कहीं आगे खड़े होंगे। उनके माता-पिता के पास पर्याप्त संसाधन होने के कारण वह उच्च शिक्षा हेतु निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने भविष्य को संवारने में लग जाएंगे। इनमें से कई तो विदेशों में जाकर बसने की सोच लेते हैं। आजकल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जो कक्षा 12 वीं के बाद ही सीधे स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई हेतु प्रवेश को आसान बनाने के लिए उनके लिए आई बी का परीक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। इन विद्यालयों का वार्षिक शुल्क 3 लाख रुपए से 30 लाख तक का हो सकता है।

अपनी शिक्षा पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के बाद, शिक्षा पूरी होते ही, उसे किस प्रकार समाज से वसूल करें, यही मुख्य ध्येय हो जाता है। ऐसा करने में, चाहे गरीब परिवारों का शोषण ही क्यों न करना पड़े? जिस प्रकार के कॉर्पोरेट अथवा निजी चिकित्सालय इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त परिवारों के बच्चों द्वारा खोले गए हैं, वे अन्य व्यवसाय की तरह ही मुनाफा कमाने के माध्यम बनकर रह गए हैं। सबको स्वास्थ्य सुलभ कराने का सपना, जनता से दूर करने में, ऐसे निजी अस्पताल संचालकों की बहुत बड़ी भूमिका है।

प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार एवं, शिक्षाविदों और नीति निर्धारकों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सभी परिवारों के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा उपलब्ध कराए बिना संभव नहीं हो सकता है। हम 142 करोड़ व्यक्तियों को देश होने का दम भरते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कई बार अनेक स्तरों पर सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में होने को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। यह जनसंख्या, तभी भारत को मजबूत और विकसित बनाने में योगदान कर पाएगी, जब इन सबको समान रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल तो ऐसा करना कई वर्षों तक संभव नहीं लगता क्योंकि किसी भी दल द्वारा अपने चुनाव प्रचार में अच्छी और समान शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की बात तक नहीं की जाती है। किसी भी दल के घोषणा पत्र में इस बारे में कोई उल्लेख तक नहीं होता कि वह सत्ता में आने पर सबको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएंगे।

मूल्यतु सुविधाओं से वंचित विद्यालय, पर्याप्त शिक्षकों के अभाव एवं माता-पिता के शिक्षित न होने से उन्नत शिक्षण के अभाव में, किस प्रकार के नागरिक समाज में बड़े होकर बनेंगे, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। समाज में जिस प्रकार से अपराध और वगैर संघर्ष बढ़ रहा है उसमें और तेजी से वृद्धि होगी, यदि हम अधिकांश जनसंख्या को अच्छी शिक्षा प्रत्येक स्तर पर प्रदान नहीं कर पाएंगे।

इसका हल केवल यही है कि सरकार अगले 10 वर्ष सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस हेतु, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य केवल निजी संस्थाओं के भरोसे छोड़ देने से शिक्षा में असमानता को, सरकार, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा ही देगी। असमान शिक्षा, देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। यह बात सबको अब भी समझ में नहीं आई तो फिर विकसित राष्ट्र का सपना केवल जुमला ही बनकर रह जाएगा। जब सबको समान अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब ही सब किसी उपयोगी कार्य में संलग्न हो पाएंगे। तब, बेरोजगारी की समस्या भी नहीं रहेगी। इसके लिए न केवल राज्य स्तर पर शिक्षा और विद्यार्थी के अनुपात को ठीक करना होगा अपितु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समुचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। शिक्षक-प्रशिक्षण को भी आमूल चूल रूप से बदलना होगा ताकि वे बच्चों को खोजें एवं जिज्ञासु बनने हेतु प्रोत्साहित कर सकें।

सर्वाधिक उपयुक्त तो यह होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने सार्वजनिक संबोधनों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात करना प्रारंभ करें एवं इस हेतु बजट की किसी भी प्रकार की समस्याओं को बस नहीं आने दें। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जो तय कर लेते हैं, उसे कर गुजरने की क्षमता भी रखते हैं। इस केवल उन्हें अपनी इस क्षमता और शक्ति का प्रयोग देश में समान शिक्षा प्रदान करने की दिशा में करने की आवश्यकता है। सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हाथ में रखते हुए अन्य सभी क्षेत्रों में निजीकरण कर दे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। सरकार को कई प्रकार के व्यवसाय के कामों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह मूल रूप से शासन की जिम्मेदारी है। यही वह बात है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मौल का पथर सिद्ध होगी।

आशा करनी चाहिए कि आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दल, शिक्षा के महत्व को समझ कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में करेंगे। शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में भी आवश्यकता के अनुसार सारे परिवर्तन किए जाने चाहिए।

देश के शिक्षकों में क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस केवल स्थानांतरण के चक्कर से उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। स्थानीय, सदैव उपलब्ध शिक्षक, बच्चों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को जोड़ पाएगा बच्चों का भविष्य देश के भविष्य के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है।

आइए, हम सब मिलकर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सरकारों पर दबाव बनाएं। ऐसा करके हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने के यत्न में अपनी आहुति दे पाएंगे।

—अतिथि सम्पादक,
राजेश भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अविनाश जोशी

सड़क हादसे जिंदगी की रफ्तार को रोक देते हैं। परिवार टूट जाते हैं एवम कई बार तो यह प्रश्न होता है की आगे की जिंदगी कैसे जी जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन देश के किसी भी भाग में सड़क हादसा न हो और कुछ लोगों को जान से हाथ न धोना पड़े। अमूमन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले आम जन होते हैं। इसलिए वे अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाते, जिससे उन दुर्घटनाओं पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। अनुमान हमारे देश में हर मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है और हर तीन मिनट में सड़क दुर्घटना में एक जान जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में ही होते हैं। जबकि चीन, रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में भारत की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में कारें हैं। दुर्घटनाओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पिछले दस साल में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में लगभग चालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में आबादी में सिर्फ बारह प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

नहीं थम रहे सड़क हादसे

ज्यादातर मौतें दो-पहिया वाहनों की दुर्घटना में हुई हैं और तेज व लापरवाही से वाहन चलाना उनकी वजह रही है।

आज के युग में विज्ञान ने मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल बना दिया है उससे उतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता जितना पहले करना पड़ता था हर क्षेत्र में आज मनुष्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करता है वाहन भी विज्ञान की ही देन है जिसके माध्यम से आज हम एक दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं परंतु इन्हीं भावनाओं के कुछ नुकसान भी हैं वायु को दूषित करने के अतिरिक्त सड़क दुर्घटना भी इन्हीं वाहनों की देन है। सड़क सुरक्षा के मानकों का महत्व समझना और समझाना दोनों जरूरी है, क्योंकि देश में सड़क नेटवर्क का तेजी से हो रहे विस्तार, गाड़ियों की संख्या में हो रही वृद्धि और शहरीकरण का नकारात्मक पक्ष सड़क दुर्घटनाओं के रूप में सामने आ चुका है। सड़क हादसों में होने वाली मौतें और अंगणता की बढ़ती संख्या ने यह सोचने पर विवश किया है कि क्या विकास की धुरी मानी जानी वाली सड़कें मौत का प्रमुख कारण और जगह बनती जा रही हैं?

हमारी सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण के उचित कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही वाहनों की सुरक्षा के मानकों को समय-समय पर जांच होनी चाहिए। परी वहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को परमिट दिए जाने की प्रक्रिया में कड़ाई बरती जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की

जाए, साथ ही छोटे बच्चों और किशोरों के वाहन चलाने पर कड़ाई से रोक लगे। तेज रफ्तार, सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग न करने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरूकता अभियान चलाए जाएं, तभी भारत में सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी।

शहरों में लालबत्ती पार करने, अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने और आगे निकलने की प्रवृत्ति आम है। यह दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने जैसा है। इससे सैकड़ों लोग घायल होते और मरते हैं। इसमें यातायात पुलिस की लापरवाही कम जिम्मेदार नहीं है। वहीं हादसा होने के बाद घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में हुई देरी घायल व्यक्ति को मौत का बड़ा कारण है, मगर आम लोग घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं आते। राज्य सरकार की तरफ से घायल को तत्काल चिकित्सा और राहत पहुंचाने वाली सुविधाएं भारत में बहुत कम हैं।

पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा संबंधी कई उपाय किए हैं। उनमें सुरक्षित बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करना, जागरूकता पैदा करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा सूचना का डेटाबेस तैयार करना जैसे उपाय शामिल हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मगर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने इन सारे उपायों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वजह है कि इन उपायों का पालन ठीक से नहीं कराया जा रहा है। कठोर

कानून के बावजूद लोगों को उसका भय नहीं सताता, जिसका परिणाम प्रतिदिन सैकड़ों सड़क हादसों के रूप में सामने आता है। विडंबना ही कही जाएगी कि जो सुझाव सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात विशेषज्ञों द्वारा दिए जाते रहे हैं उन्हें मुस्तेदी के साथ पालन करने के लिए यातायात पुलिस कुछ दिन तो काम करती है, लेकिन धीरे-धीरे फिर वही पुराना ढर्रा कायम हो जाता है। वरना क्या कारण है कि भारत में ही सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं?

विश्व के कुल वाहनों का महज दो फीसदी भारत में है, पर सड़क हादसों में होने वाली मौतें बारह फीसदी से ज्यादा हैं। दुनिया के तमाम देशों ने अपने कड़े सड़क कानून और जनजागरूकता अभियानों के जरिए सड़क हादसों में वृद्धि नहीं होने दी, लेकिन पिछले बीस सालों में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भारत में पचहत्तर फीसद से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में कितना सड़क कानूनों का पालन किया और कार्या जाता है। सड़क सुरक्षा पर जारी की गई विश्व स्थिति रिपोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामले की मुख्य पांच वजहें बताई हैं। इनमें सीमा से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, सुरक्षा पेटी न बांधना, दुर्घटिया चलाते वक्त हेलमेट न पहनना और बच्चों की सुरक्षा के उपायों की अनदेखी शामिल है।

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक नब्बे फीसदी हादसे ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं। इस पर यह सवाल उठाना लाजिमी है कि

क्या ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त कायदे से जांच-परख की जाती है? क्या सुरक्षा मानकों पर गाड़ियों की कड़ी जांच-पड़ताल होती है? ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर क्या और सख्ती होनी चाहिए? भारत में रोज तेरह सौ से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर दिन सड़क हादसों में करीब चार सौ मौतें होती हैं। सड़क हादसों में सालाना करीब अरब डॉलर का नुकसान होता है।

भारत में बारह करोड़ से ज्यादा वाहन हैं और इनके चलने के लिए पर्याप्त सड़कें होना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोका जा सकता है? जिस तरह देश-समाज की सुरक्षा वाले कानूनों का पालन महज दिखावा बन कर रह गया है वैसे ही यातायात नियमों की अनदेखी एक प्रवृत्ति बन गई है। यातायात नियमों का पालन, अतिरिक्त सावधानी, वाहन को नियंत्रित सीमा में रखना, पैदल यात्रियों का सड़क पार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना, सड़कों को मानक रूप में बेहतर बनाए रखना और 'ओवरटेक' करने से बचना जरूरी है। सड़क सुरक्षा सप्ताहों में जिस तरह पुलिस यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक और बाध्य करता है, वैसी जागरूकता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो हादसों में कमी लाई जा सकती है।

—अविनाश जोशी,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

बड़गांव व रघुनाथपुरा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

विकास कार्य नहीं होने पर वार्ड पंचों ने इस्तीफे की धमकी दी

अजमेर, (कासं)। विनाय पंचायत समिति से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम बड़गांव व रघुनाथपुरा की अच्छी खासी आबादी है। चुनाव के दिनों में नेता लोग यहां दिन भर चक्कर काटते हैं। बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन अब हालत देखें तो गांव पर तरस आता है। लेकिन न तो इस हालत को देखने के लिए नेता आते और न ही कभी कोई अफसर विकास कार्य की कमी के चलते यह दोनों गांव पिछड़ता नजर आ रहा है। सरकार के समान विकास के वादे झूठे साबित हो रहे हैं।

ग्रामीणों तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके साथ सौतेला यामिन हो रहा है। गांव की सरकार यामिन प्राप्त करने के कार्यकाल को भी करीब तीन साल गुजर चुके हैं। लेकिन गांव के हालात जस के जस हैं। अच्छी सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के दायित्व से सरकारों ने लगता है, मुंह मोड़ लिया है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में लगभग सारे विद्यालय सरकारी हैं। भारत में भी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि सरकार चाहे तो शिक्षा विद्यालय संचालित कर सकती है।

दृश्य एक में उल्लिखित विद्यालय अमीर, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए सीमित होकर रह गए हैं। स्वाभाविक है, जो विद्यार्थी ऐसे विद्यालय से निकलेंगे, वे जीवन की हर दुर्घटना में अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में पहले से ही कहीं आगे खड़े होंगे। उनके माता-पिता के पास पर्याप्त संसाधन होने के कारण वह उच्च शिक्षा हेतु निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने भविष्य को संवारने में लग जाएंगे। इनमें से कई तो विदेशों में जाकर बसने की सोच लेते हैं। आजकल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जो कक्षा 12 वीं के बाद ही सीधे स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई हेतु प्रवेश को आसान बनाने के लिए उनके लिए आई बी का परीक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। इन विद्यालयों का वार्षिक शुल्क 3 लाख रुपए से 30 लाख तक का हो सकता है।

अपनी शिक्षा पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के बाद, शिक्षा पूरी होते ही, उसे किस प्रकार समाज से वसूल करें, यही मुख्य ध्येय हो जाता है। ऐसा करने में, चाहे गरीब परिवारों का शोषण ही क्यों न करना पड़े? जिस प्रकार के कॉर्पोरेट अथवा निजी चिकित्सालय इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त परिवारों के बच्चों द्वारा खोले गए हैं, वे अन्य व्यवसाय की तरह ही मुनाफा कमाने के माध्यम बनकर रह गए हैं। सबको स्वास्थ्य सुलभ कराने का सपना, जनता से दूर करने में, ऐसे निजी अस्पताल संचालकों की बहुत बड़ी भूमिका है।

प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार एवं, शिक्षाविदों और नीति निर्धारकों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सभी परिवारों के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा उपलब्ध कराए बिना संभव नहीं हो सकता है। हम 142 करोड़ व्यक्तियों को देश होने का दम भरते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कई बार अनेक स्तरों पर सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में होने को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। यह जनसंख्या, तभी भारत को मजबूत और विकसित बनाने में योगदान कर पाएगी, जब इन सबको समान रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल तो ऐसा करना कई वर्षों तक संभव नहीं लगता क्योंकि किसी भी दल द्वारा अपने चुनाव प्रचार में अच्छी और समान शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की बात तक नहीं की जाती है। किसी भी दल के घोषणा पत्र में इस बारे में कोई उल्लेख तक नहीं होता कि वह सत्ता में आने पर सबको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएंगे।

मूल्यतु सुविधाओं से वंचित विद्यालय, पर्याप्त शिक्षकों के अभाव एवं माता-पिता के शिक्षित न होने से उन्नत शिक्षण के अभाव में, किस प्रकार के नागरिक समाज में बड़े होकर बनेंगे, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। समाज में जिस प्रकार से अपराध और वगैर संघर्ष बढ़ रहा है उसमें और तेजी से वृद्धि होगी, यदि हम अधिकांश जनसंख्या को अच्छी शिक्षा प्रत्येक स्तर पर प्रदान नहीं कर पाएंगे।

इसका हल केवल यही है कि सरकार अगले 10 वर्ष सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस हेतु, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य केवल निजी संस्थाओं के भरोसे छोड़ देने से शिक्षा में असमानता को, सरकार, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा ही देगी। असमान शिक्षा, देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। यह बात सबको अब भी समझ में नहीं आई तो फिर विकसित राष्ट्र का सपना केवल जुमला ही बनकर रह जाएगा। जब सबको समान अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब ही सब किसी उपयोगी कार्य में संलग्न हो पाएंगे। तब, बेरोजगारी की समस्या भी नहीं रहेगी। इसके लिए न केवल राज्य स्तर पर शिक्षा और विद्यार्थी के अनुपात को ठीक करना होगा अपितु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समुचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। शिक्षक-प्रशिक्षण को भी आमूल चूल रूप से बदलना होगा ताकि वे बच्चों को खोजें एवं जिज्ञासु बनने हेतु प्रोत्साहित कर सकें।

सर्वाधिक उपयुक्त तो यह होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने सार्वजनिक संबोधनों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात करना प्रारंभ करें एवं इस हेतु बजट की किसी भी प्रकार की समस्याओं को बस नहीं आने दें। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जो तय कर लेते हैं, उसे कर गुजरने की क्षमता भी रखते हैं। इस केवल उन्हें अपनी इस क्षमता और शक्ति का प्रयोग देश में समान शिक्षा प्रदान करने की दिशा में करने की आवश्यकता है। सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हाथ में रखते हुए अन्य सभी क्षेत्रों में निजीकरण कर दे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। सरकार को कई प्रकार के व्यवसाय के कामों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह मूल रूप से शासन की जिम्मेदारी है। यही वह बात है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मौल का पथर सिद्ध होगी।

आशा करनी चाहिए कि आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दल, शिक्षा के महत्व को समझ कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में करेंगे। शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में भी आवश्यकता के अनुसार सारे परिवर्तन किए जाने चाहिए।

देश के शिक्षकों में क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस केवल स्थानांतरण के चक्कर से उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। स्थानीय, सदैव उपलब्ध शिक्षक, बच्चों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को जोड़ पाएगा बच्चों का भविष्य देश के भविष्य के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है।

आइए, हम सब मिलकर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सरकारों पर दबाव बनाएं। ऐसा करके हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने के यत्न में अपनी आहुति दे पाएंगे।

तस है। वास्तव में कोई सुधार गांव में नहीं हुआ है।

ग्राम सुरखंड बड़गांव के वार्ड 3 के पंच विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे हर समय गांव की गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। इसके अलावा लगभग हर गली निर्माण न होने के कारण पुंगु हाल है। गांव की ज्यादातर गलियां खस्ता हाल में हैं। हर समय कीचड़ भरा रहता है। गांव की शायद ही कोई गली ऐसी हो जिसमें कीचड़ न भरा हो। इन सबके चलते गांव की वर्तमान स्थिति बेहद खराब है। गांव की गलियों से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है।

ग्राम पंचायत के पांचों ने सोमवार को सचिव दुलाराम जांगिड़ को ज्ञापन सौंप कर अवगत करवाया कि

■ सचिव को सौंपा ज्ञापन, सड़क व नाली निर्माण की मांग

ग्रामवासियों ने बड़गांव में विकास कार्य करवाने के लिए हमारे ऊपर विश्वास करने हेतु वार्ड पंच चुना, लेकिन गांव में विकास कार्य नहीं होने कारण ग्रामवासियों के विश्वास पर हम खरे नहीं उतर पाए। इसलिए आए दिन हमें ग्रामवासियों की गलियों व ताने सुन-सुन कर कान पक गए।

विगत तीन वर्षों से ना तो पक्का काम चला और न ही चलने की संभावना दिख रही है। ग्राम बड़गांव में नालियां, पुलिया व सीसी सड़क आदि की ग्राम

बड़गांव में जरूरत होने के बावजूद पंचायत प्रशासन का ध्यान होते हुए भी आंच पर पट्टी बांध कर नजर अंदाज किया जा रहा है। जबकि ग्राम पंचायत के फंड में पैसा थड़ा है। ग्राम सभा व वार्ड सभा में प्रस्ताव लिए जाते हैं, लेकिन काम नहीं किया जाता है। फिर ग्राम सभा व वार्ड सभा मार कर का क्या महत्व सरकार द्वारा गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सड़कें व नालियां टूटी हुई होने के कारण कीचड़ व गंदगी पूरे गांव में फैली हुई है। बार-बार इन विकास कार्यों के लिए पंचायत प्रशासन को अवगत करवाने व निवेदन करने के बाद भी चक्कर पर चक्कर दिए जा रहे हैं। कुछ कार्यों की छह माह पूर्व स्वीकृति निकालने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा

ग्राम रघुनाथपुरा व बड़गांव के ग्रामवासियों के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। वार्ड पंचों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों पर 15 दिवस में स्वीकृति व स्वीकृति निकले हुए कार्यों पर काम नहीं चलाया गया तो हम सभी वार्ड पंच एक साथ इस्तीफा देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंचायत प्रशासन की होगी। इस दौरान वार्ड दो पदम भील, वार्ड तीन के विष्णुदत्त शर्मा, वार्ड चार के महावीर सोनी, वार्ड पांच रामकाना मेघवर्षी, वार्ड छह के लाडा देवी, वार्ड सात के धनराज जाट सहित बड़ी संख्या में वार्ड पंच उपस्थित रहे। सचिव दुलाराम जांगिड़, ग्राम पंचायत बड़गांव का कहना है कि जिन कार्यों की स्वीकृति निकाली गई है, उन कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करवा दिया जाएगा।

“वंदे भारत ट्रेन” हादसे का शिकार होने से बची

भीलवाड़ा, (निंसां)। हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन सोमवार सुबह बदमाशों की करतूत के चलते दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। घटना, गंगार और सोनियाणा स्टेशनों के बीच हुई। गनीमत रही कि ट्रेन के पायलेट और सहायक की नजर पथरों पर पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन सोमवार सुबह उदयपुर से रवाना होकर करीब साढ़े नौ बजे सोनियाणा-गंगार रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक पोल् 158/18-19 से कुछ दूरी पर पहुंची थी कि ट्रेन के पायलेट व सहायक की नजर ट्रेक पर रखे पथरों व ट्रेक के बीच गढ़े कीलों पर पड़ गई। चालक ने सतर्कता बरते हुए ट्रेन को ब्रेक लगाकर इन पथरों व कीलों से 5-7 मीटर की दूरी पर रोक लिया। इससे यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। यहां दोनों ट्रेक पर करीब दस मीटर की दूरी तक मिट्टी पथर रखे

■ बदमाशों की करतूत, यह घटना गंगार और सोनियाणा स्टेशनों के बीच हुई

■ पायलेट और सहायक की नजर पथरों पर पड़ गई, हादसा टला

हुये मिले और दो कीलें दोनों पटरियों के बीच गढ़े हुये थे। पायलेट व सहायक ने इंजन से उतर कर ट्रेक से पथर व कीले हटाये और इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों के साथ ही रेलवे सुरक्षा बल को दी। करीब 10 मिनट खड़ी रहने के बाद वंदे भारत ट्रेन भीलवाड़ा के लिए रवाना हुई। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी व रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरु की है।



रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी व रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरु की।

राशिफल मंगलवार 3 अक्टूबर, 2023

मंत्री ओला ने भामाशाहों का सम्मान व विकास कार्यों का लोकार्पण किया

झुंझुनू, (निसं)। झुंझुनू विधानसभा के ग्राम किशोरपुर में सोमवार को विद्यालय प्रोग्राम में ग्रामवासियों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्री वृजेन्द्र ओला का अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया। ग्रामवासियों की ओर से किये गए भव्य स्वागत से अभिभूत मंत्री ओला ने अपने संबोधन में कहा कि उनके परिवार ने किशोरपुर पंचायत के विकास में आज तक कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी आप द्वारा विकास कार्यों से सम्बंधित किसी भी आदेश को तत्परता से पूर्ण करवाया जायेगा। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र झाझडिया की अध्यक्षता व पूर्व पार्षद भगवती डारा, सरजीत ओला, गिडानिया कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुमेर सिंह महला, मोहरसिंह सोलाना, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुनील जानू, सुशील पायल, पीएमओ कमलेश झाझडिया, पूर्व सचिव निदेशक पितराम सिंह काला, सरपंच अनिल श्योराम के मुख्य आतिथ्य में आयोजित अभिनन्दन समारोह के दौरान मंत्री ओला ने नवनर्मित अम्बेडकर भवन, स्मार्ट



मंत्री ओला ने स्वागत समारोह को संबोधित किया।

क्लासरूम, स्टेज व टीनशेड का लोकार्पण भी किया। इससे पूर्व मंत्री ओला ने नगरपरिषद झुंझुनू के पूर्व पार्षद भगवती डारा, पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा व पुलिस निरीक्षक रविन्द्र प्रताप डारा द्वारा पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी स्व. सुलतान सिंह डारा की स्मृति में बनाये गए खेल मैदान के मुख्य द्वार का लोकार्पण भी किया।

मंत्रि ओला ने डारा परिवार द्वारा बनवाये गए द्वार के लिये उन्हें साधुवाद देते हुए उनके द्वारा आगे भी गांव के विकास में सक्रिय रहने के आश्वासन की सराहना भी की। कार्यक्रम में मंत्री ओला का ग्रामवासियों व मेघवाल समाज द्वारा 31 व 21 किलो की माला पहनकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री ओला ने विद्यालय विकास के लिये सहयोग करने वाले 21 भामाशाहों का शॉल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर स्वागत

21 भामाशाहों का शॉल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया

करते हुए उनका विशेष आभार जताया। विद्यालय के प्रतिभावन विद्यार्थियों को भी इस अवसर पर चांदी के सिक्के देकर समानित किया गया। प्रधानाचार्य चंद्रपाल सिंह डारा ने स्वागत सम्बोधन दिया और रविन्द्र प्रताप डारा ने अपने सम्बोधन में मंत्री ओला का आभार जताते हुए गांव के विकास के लिये उनके परिवार को हर समय मौजूदगी का भरपूर आभार दिया। इस अवसर पर धर्मपाल डारा, पूर्व उपसरपंच बजरंग, सुभाष चन्द्र, सुबेदार जलेश, मंगतू मेघवाल, मदन, दयाकिशन डारा, महेंद्र डारा, रणधीर, महेंद्र मेघवाल, दलीप सिंह डारा, अशोक डारा, नरेन्द्र डारा, विक्रम सिंह डारा, बिरबल मेघवाल, मदन मेघवाल व टीम डारा के सैकड़ों सदस्यों सहित पंचायतवासी व सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही।

गांधी जयंती के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

हनुमानगढ़, (निसं)। रा.सा, जयपुर द्वारा स्टेट एक्शन प्लान में दिये गये निर्देशानुसार अरुण जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ धनपत माली, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय सावित्री बाई फूले महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास में गांधी जयंती के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



सावित्री बाई फूले छात्रावास में गांधी जयंती के अवसर पर छात्राओं को सम्बोधित करते न्यायाधीश धनपत माली।

न्यायाधीश धनपत माली ने छात्राओं को जानकारी दी

"सादा जीवन, उच्च विचार" था। गांधी जी कभी किसी को जात-पात से तोलकर नहीं देखते थे, उनके लिए हर व्यक्ति बराबर था। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत शांति की संस्कृति का निर्माण करना, अहिंसक असहयोग की

प्रभावशीलता को साबित करना था गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कई आंदोलन किये और "करो या मरो" व "अहिंसा परमो धर्म" जैसे नारे दिये। हमें गांधी जयंती पर अहिंसा के मार्ग पर चलने, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण काम करने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर छात्राओं द्वारा कविता, संगीत की प्रस्तुतियां दी तथा छात्रावास अधीक्षक द्वारा भी गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला।

ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करेंगे शिक्षक

चूखू, (कासं)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने 2 अक्टूबर से शाला दर्पण शिक्षक एप्स से छात्रों व शिक्षकों की

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने निर्णय लिया

अनिवार्य उपस्थिति का विरोध करने का निर्णय लिया है। संगठन का मानना है कि विभागीय नियमानुसार प्रथम कालांश कठिन विषयों का होता है। राजस्थान के रिमोट एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। ऐसी परिस्थितियों में ऑनलाइन हाजरी करने में ही कालांश निकल जाएगा। जिला मंत्री शिवकुमार शर्मा ने बताया कि विभाग ने ना तो शिक्षकों को एंड्रॉइड मोबाइल फोन उपलब्ध कराया है और ना ही डाटा पैक की व्यवस्था की है। बिना प्रशिक्षण के यह कार्य थोपा जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी व मण्डल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह ने कहा कि इससे शिक्षकों की निजता का भी हनन होता है जबकि विभाग ने साइबर सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं दी है।

शिविर में 129 यूनिट रक्तदान

चिड़वावा। शहर की सूरजगढ़ बाईपास स्थित डीएसएम अस्पताल में ब्लड बैंक लगाया। शिविर आयोजन समिति के पवन शर्मा और अमित सैनी ने बताया कि शिविर में रक्तदान के प्रति युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश शर्मा (शेर) नरहड के जन्म दिवस पर लगे हुआ रक्तदानों को भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया, सुरेश भूकर, पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा, पितराम काला, समाजसेवी शीशराम हलवाई, पूर्व प्रधान निहाल सिंह रणवा, रोहितारण रणवा, अध्यक्ष प्रमोद सागवान, रतन चौधरी, लोकेश डूडी, नगरपालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह आदि ने सम्मानित किया। इस दौरान सरला पाठशाला की अनिता पुनिया, भाजपा नगर अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पूर्व प्रधान डारा, सरपंच कृष्ण यादव कलगांव, प्रकाश गुर्जर, राजेंद्र भास्कर गाडखेडा, राजेंद्र सैनी, नरेश सैनी, राधेश्याम सुखाडिया, डॉ. देवेन्द्र चाहर, डॉ. शिवा चाहर और महिलाओं ने भी बढ़कर चढ़कर भाग लिया। चंपालाल शर्मा, सोहनलाल शर्मा, जगदीश शर्मा ने सभी का धन्यवाद जताया।

सभापति पायल सैनी ने किया सी.सी. सड़कों का लोकार्पण



जिला मुख्यालय पर वार्ड 55 में सभापति पायल सैनी ने तीन सीसी सड़कों का लोकार्पण किया।

चूखू, (कासं)। जिला मुख्यालय पर वार्ड 55 में सभापति पायल सैनी ने तीन सीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्म दिवस पर केक काटा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने की।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि युवा नेता इरशाद मंडेलिया, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नारायण बालाण, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोबर, अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अन्वारी, शारदा चोटिया, सद्दाम हुसैन, पार्षद प्रतिनिधि अजीज खान दिलावरखानी, पार्षद प्रतिनिधि लोकेश सैनी, पार्षद बाबु मंत्री, पार्षद प्रतिनिधि विजय सारस्वत, पार्षद विनोद खटीक, पार्षद गोकुल शर्मा, आबिद खान,

तारीक नागौरी, तौफीक खान, रामेश्वर प्रसाद नायक, मण्डल अध्यक्ष हमीद खान रिसालदार, लालचंद चोटिया, राजकीय लोहिया कालेज महासचिव अनिस खान आदि थे।

इस अवसर पर सदर अख्तर अली चेजारा, सचिव अब्बास चेजारा, लालचंद चोटिया, राजकुमार चोटिया, अमित सिंधी, विककी सिंधी, इकबाल सिसोदिया, अलताफ रंगरेज, इलियास सिसोदिया, कैलाश गोईन्का, शंकरलाल, महेश सिंधी, लालचंद शर्मा, सत्तार कुरेशी, उस्मान गन्नी, मंगतु लुहार, अज्जु लुहार, सुलेमान मणिया, निसार खान, नौसाद खान, मुकेश कुमार, राजेश, सलीम पीए, मुस्तकीम कुरेशी, आरिफ सिसोदिया, मोहम्मद आसिफ, फैसल, कबीर, नदीम, इमरान, साजिद, सलीम गुर्जर, राजु गुर्जर, समीर गुर्जर, शकूर गुर्जर, सिकंदर गुर्जर, जाफर रंगरेज, सलमान रंगरेज सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने किया। इस अवसर पर धर्मचंद सिंधी व लालचंद चोटिया ने सभी का आभार व्यक्त किया।

डोटासरा ने सरकार की नीतियों का संगठन के साथ तालमेल बैठाय़ा : मुस्ताक खान

चूखू, (कासं)। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन प्रदेश सचिव मुस्ताक खान ने कांग्रेसजनों की मौजूदगी में झुग्गी-झोंपड़ियों के बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। प्रदेश सचिव मुस्ताक खान ने बताया कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ भोजन करके डोटासरा की गरीबों को गणेश मानकर कार्य करने की रीति-नीति के अनुसार उनका जन्म दिन मनाया है। मुस्ताक खान ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की नीतियों को संगठन के साथ तालमेल बैठाकर जन-जन तक पहुंचाया एवं भाजपा नेताओं को उनके घर में जाकर घेरेने की रणनीति बनाई। खान ने कहा कि इसी के सहारे कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। पार्षद अंजनी शर्मा ने संचालन किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश दूकिया, यूथ कांग्रेस तहसील उपाध्यक्ष पुलकित चौधरी, सतीश शास्त्री, मुबारिक भाटी, अब्बास काजी, सलीम



झुग्गी-झोंपड़ियों के बच्चों के साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन मनाते प्रदेश सचिव मुस्ताक खान।

काजी, पार्षद यासिन चौहान, आबिद मोयाल, विजेन्द्र सिंह सरपंच, नरेश शर्मा, लेखराम, राजकुमार शर्मा, हरफूल, जगल सैनी, कैलाश बाल्मीकि, लालचंद मेघवाल, ताराचंद सैनी, गोपालराम

कस्वां, राहुल मुहाल, अकरम खान, ताराचंद मेघवाल, पुरुषोत्तम मेघवाल, रोहित मुहाह, मनोज नायक, तिकोल पुनिया, मखन लाल पिलानिया, जेपी कस्वां, उंपेंद्र सिंह राठौड, कय्यू खान,

कांग्रेसजनों ने झुग्गी-झोंपड़ियों के बच्चों के साथ मनाया गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन

समद खान, रहमत खान, आदिल, समीर खान, साहिल, वसीम सोयल, अकरम खान, शाहाबाद, अनीश खान, फरमान खान, सोहेल खान, आसिफ खान इसेखानी, मोहसिन खान, साजिद नारू, बिलाल मोयल, जमील खान, शकील खान, फारूक खान, अय्यूब चौहान, राजा खान, मोहसिन खान, अरमान एलमान, शोएब एलमान, तारिक खान, इरफान खान, अमजद खान, आबिद खान, जावेद खान, अज्जुदिन खोबर, मोहम्मद तौफीक, आदिल, महबूब, तौफीक भाटी, समीर नाई, समीर काजी आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर परिषद्, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक:- एफ-6 भूमि () /2023-24/14

दिनांक:-30.09.2023

-: सार्वजनिक आपत्ति विज्ञप्ति :-

निम्न आवेदकों के द्वारा उनके नाम के सामने अंकित कृषि भूमि नियमन/उप विभाजन पुर्नगठन चाहने बाबत इस परिषद् में आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। वांछित स्वीकृति/आदेश जारी करने से पूर्व इस संबंध में आपत्ति प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस में आपत्तियां मय सबूत आमंत्रित की जाती है। बाद मियाद आपत्तियां विचारणीय नहीं होगी।

क्र. सं.	नाम आवेदक/आवेदिका	वांछित स्वीकृति का विवरण	सम्पत्ति का विवरण जिसके संबंध में स्वीकृति चाही जा रही है	ऑनलाईन पत्रावली क्रमांक
1	मगनाराम/हरदेवाराम	कृषि भूमि नियमन	सैनिक नगर संशोधित भू.स. 355डी का भाग का क्षेत्रफल 330.66 वर्गगज	170868
2	शिशाराम/कन्हैयालाल	कृषि भूमि नियमन	शिवकॉलोनी भाग-2 भू.स. 130 का क्षेत्रफल 168.33 वर्गगज	170657
3	रंजना/सुरेन्द्रसिंह	कृषि भूमि नियमन	सैनिक नगर भू.स. 232बी का क्षेत्रफल 108.58 वर्गगज	170659
4	विरेंद्र कुमार /महावीर सिंह	कृषि भूमि नियमन	विवेक नगर भू.स. 79 का क्षेत्रफल 248.33 वर्गगज	170669
5	रघुवीर सिंह/जयकिशन	कृषि भूमि नियमन	खाजपुर रोड व इण्डाली रोड के आस पास का भाग-6 भू.स. 131ए का क्षेत्रफल 200 वर्गगज	170544
6	बाबूलाल/छत्रपालसिंह	कृषि भूमि नियमन	सीकर रेल्वे लाईन के उतर का भाग भू.स. 234 का क्षेत्रफल 233.47 वर्ग.	170707
7	राजेश कुमार/रामसिंह	कृषि भूमि नियमन	सरस्वती कॉलोनी 2क भू.स. 43 का क्षेत्रफल 220.97 वर्गगज	170502
8	शब्बीर भाई/अब्दुल रजाक	कृषि भूमि नियमन	के के कॉलोनी भूखण्ड का क्षेत्रफल 218 वर्गगज	170446
9	मो. सलीम/शब्बीर भाई	कृषि भूमि नियमन	के के कॉलोनी भूखण्ड का क्षेत्रफल 233 वर्गगज	170447
10	मो. आदील/शब्बीर भाई	कृषि भूमि नियमन	के के कॉलोनी भूखण्ड का क्षेत्रफल 233 वर्गगज	170451
11	मो. अजहर/शब्बीर भाई	कृषि भूमि नियमन	के के कॉलोनी भूखण्ड का क्षेत्रफल 218 वर्गगज	170453
12	आरिफ/शब्बीर भाई	कृषि भूमि नियमन	के के कॉलोनी भूखण्ड का क्षेत्रफल 218 वर्गगज	170455
13	मो शरीफ/शब्बीर भाई	कृषि भूमि नियमन	के के कॉलोनी भूखण्ड का क्षेत्रफल 233 वर्गगज	170456
14	दरिया सिंह/दाताराम	कृषि भूमि नियमन	नायकॉन कॉलोनी भू.स. 279 का भाग का क्षेत्रफल 238 वर्गगज	170794
15	सुनिता कुमारी/विजयसिंह	कृषि भूमि नियमन	सूरज कॉलोनी अणगासर रोड भाग-1 भू.स. 146 का क्षेत्रफल 222.22 वर्ग	170716
16	तारामणी/जगदीश	कृषि भूमि नियमन	शालीमार कॉलोनी-2 भू.स. 16 का क्षेत्रफल 263.46 वर्गगज	170658
17	मुकेश कुमार/मुकुन्दसिंह	कृषि भूमि नियमन	अफसाना जोहडा व नयासर जाने वाली रोड भू.स. 38 का क्षेत्रफल 174.58 वर्गगज	170663
18	पूजा/संदीप	कृषि भूमि नियमन	शास्त्री नगर भाग-6 भू.स. 43 का क्षेत्रफल 205.33 वर्गगज	170654
19	राकेश कुमार/मनीराम	कृषि भूमि नियमन	रोड नं. 3 के उतर का क्षेत्र भू.स. 193 का भाग का क्षेत्रफल 101.11 वर्ग	170767
20	भगवती देवी/बनवारीलाल	कृषि भूमि नियमन	रोड नं. 3 के उतर का क्षेत्र भू.स. 193 का भाग का क्षेत्रफल 149.33 वर्ग	170766
21	शिशाराम/रामरख	कृषि भूमि नियमन	हवाई पट्टी सर्किल के आस पास भूखण्ड का क्षेत्रफल 288.50 वर्गगज	170641
22	विजय कुमार /अम्बिका महमिया	कृषि भूमि नियमन	मित्तल कॉलोनी भू.स. 282 का भाग का क्षेत्रफल 322.10 वर्गगज	171376
23	शबीना बानो/अनवर अली	कृषि भूमि नियमन	चूखू रोड से दक्षिण और डेयरी के पास का क्षेत्र भाग-1 भू.स. 159 का क्षेत्रफल 220 वर्गगज	171155
24	संतोष/हरलाल सिंह	कृषि भूमि नियमन	शिव कॉलोनी भाग-2 भू.स. 69ए का क्षेत्रफल 319.40 वर्गगज	171132
25	अरसद खान/जाफर खान	कृषि भूमि नियमन	डीटीओ के आस पास का क्षेत्र-2 भू.स. 84 का क्षेत्रफल 658.33 वर्गगज	171119
26	बिमला/प्यारेलाल	कृषि भूमि नियमन	सूरज कॉलोनी अणगासर रोड भू.स. 59 का क्षेत्रफल 264 वर्गगज	169487
27	पुष्पा देवी/सुरेश कुमार	कृषि भूमि नियमन	खाजपुर व इण्डाली रोड के आस पास भाग-1 भू.स. 145 का क्षेत्रफल 223.30 वर्गगज	171099
28	सरिता देवी/मांडूराम	कृषि भूमि नियमन	राजपूत कॉलोनी-2 भू.स. 200 का भाग का क्षेत्रफल 137.40 वर्गगज	171090
29	सुमन देवी/सत्यपाल	कृषि भूमि नियमन	शास्त्री नगर वारिसपुरा रोड-2 भू.स. 52 का क्षेत्रफल 171.66 वर्गगज	171087
30	सुमन देवी/सत्यपाल	कृषि भूमि नियमन	शास्त्री नगर वारिसपुरा रोड-2 भू.स. 44ए का क्षेत्रफल 204.02 वर्गगज	171085
31	सुशिला/पूर्णमल	कृषि भूमि नियमन	सूरज कॉलोनी अणगासर रोड भू.स. 19 का क्षेत्रफल 151.66 वर्गगज	170920
32	सत्यवीर सुण्डा/मंगलचंद	कृषि भूमि नियमन	अणगासर रोड व के के कॉलोनी भू.स. 169 का क्षेत्रफल 200 वर्गगज	171093
33	सुनिता/शुभकरण	कृषि भूमि नियमन	नेपालियों के कुआ के पास भूखण्ड का क्षेत्रफल 250 वर्गगज	171153
34	रूकमा देवी/मोहर सिंह	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-8 भू.स. 231 का क्षेत्रफल 186.75 वर्गगज	150332
35	द्रोपती देवी /सत्यनारायण	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-8 भू.स. 224 का क्षेत्रफल 165.55 वर्गगज	151351
36	सन्तरा देवी/राजकुमार	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-3 भू.स. 147 का क्षेत्रफल 163.10 वर्गगज	151346
37	सुमन कुमारी /सुरेन्द्र कुमार	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-3 भू.स. 76 का क्षेत्रफल 138.65 वर्गगज	143505
38	किरण देवी/विक्रम सिंह	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-7 भू.स. 36 का क्षेत्रफल 256.66 वर्गगज	144781
39	सरिता/अनिल कुमार	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-3 भू.स. 138 का क्षेत्रफल 194.66 वर्गगज	143509
40	सुमित्रा देवी /राजेन्द्र सिंह	कृषि भूमि नियमन	लिटील फ्लोर स्कूल के पास भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गगज	170910
41	सुरेश छापेला/जगदीश	कृषि भूमि नियमन	लिटील फ्लोर स्कूल के पास भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गगज	170911
42	मुकेश कुमार/राजेश कुमार, प्रदीप/ गोवर्धन सिंह	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-3 भू.स. 1 का भाग का क्षेत्रफल 235.55 वर्गगज	171006
43	कैलाशचन्द्र /जगदीश प्रसाद	कृषि भूमि नियमन	कालू मार्केट भू.स. 57 का भाग का क्षेत्रफल 228.08 वर्गगज	171025
44	मोहम्मद युसुफ /मो. रमजान	कृषि भूमि नियमन	कमर कॉलोनी भू.स. 21 का क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज	170895
45	भगवती देवी/महेशचन्द्र	कृषि भूमि नियमन	किसान कॉलोनी भू.स. 721 का क्षेत्रफल 400 वर्गगज	170894
46	जोगेन्द्र सिंह/रामदेव	कृषि भूमि नियमन	श्याम नगर गुडा रोड-7 भू.स. 185 का क्षेत्रफल 191.66 वर्गगज	170893
47	इकबाल/बसीर खां	कृषि भूमि नियमन	कमर कॉलोनी भू.स. 30 का क्षेत्रफल 161.11 वर्गगज	170875

आयुक्त नगर परिषद्, झुंझुनू

बैंक कर्मचारियों ने 41 लाख की राशि की हेराफेरी की

दोनों कर्मचारियों ने ऑनलाइन जुएं में 41 लाख रुपए की राशि उड़ाई

हिण्डौन सिटी, (कासं)। यूनिन बैंक ऑफ इंडिया की हिण्डौन शाखा के कर्मचारियों द्वारा 41 लाख रुपए हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। बैंक के दो कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन जुएं में 41 लाख रुपए की राशि उड़ा दी गई। मामले में बैंक के मैनेजर जितेंद्र मोघा ने हिण्डौन नई मंडी थाने में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

नई मंडी थाना अधिकारी बृजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिन बैंक ऑफ इंडिया की हिण्डौन शाखा के मैनेजर जितेंद्र मोघा ने रिपोर्ट

■ बैंक मैनेजर ने हिण्डौन नई मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जांच शुरू

■ 30 सितंबर को बैंक का कैश चैक करने पर 41 लाख रुपए की नगदी कम मिली

पेश कि है कि 30 सितंबर को बैंक का कैश एसबीआई की चेस्ट बैंक शाखा में भेजने वाले थे। उस समय पाया गया कि

बैंक में 41 लाख रुपए की नगदी कम है। कैश बैलेंस बुक में मिलान करने के बाद 41 लाख नगदी कमी की पुष्टि हुई। इसके बाद कैशियर से पूछताछ की तो उसने बताया कि रुपये उसने ही लिए हैं तथा वह उसे जल्द जमा कर देगा।

थानाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक तपतीश में पता चला है कि जगदेव डगुर ऑनलाइन जुआ खेलता था। 30 सितंबर को बैंक के कैश के लेनदेन का कार्य कर्मचारी प्रेम मोघा कर रहा था। जगदेव डगुर ने प्रेम मोघा के सहयोग से तीन-चार बार में 41 लाख रुपए की राशि बैंक से ली तथा उसे जुएं

में लगा दिया और वापस बैंक में आकर बैट गया। शाम को बैंक की राशि एसबीआई की चेस्ट में जमा करने के लिए जब कैश संभाला गया तो उसमें 41 लाख रुपए कम मिले। मैनेजर ने जब इन कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि रुपये उन्होंने लिए हैं तथा पैसे जल्द आ जाएंगे। शाम को 7 बजे तक इंतजार करने के बाद भी जगदेव ने रुपये बैंक में जमा नहीं कराए तो रविवार को बैंक मैनेजर जितेंद्र मोघा ने हिण्डौन नई मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस मामले की जनता से जांच पड़ताल में जुटी है।

जालोर व सांचोर जिले की दो विधानसभा सीटों पर हमेशा जातिगत राजनीति रहती है हावी

जालोर, (कासं)। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी सक्रिय होकर चुनाव जीतने को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जालोर व सांचोर जिले की दो विधानसभा सीटों पर हमेशा जातिगत राजनीति हावी रहती है। वहीं दोनों पार्टियों भी जातिगत आधार पर टिकट देती आई है, लेकिन इस बार भाजपा व कांग्रेस टिकट चयन को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। भाजपा के इस गढ़ को ढहाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में टिकट चयन को लेकर भी बड़ी ही सतर्कता बरती जा रही है।

प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा दोनों प्रमुख दल सत्ता में आने को लेकर समीकरण बेटाने का प्रयास कर रहे हैं। जालोर विधानसभा सीट एससी होने के साथ मेघवाल जाति का बहुल होने से

■ दोनों पार्टियां भी जातिगत आधार पर टिकट देती आई है, लेकिन इस बार भाजपा व कांग्रेस टिकट चयन को लेकर असमंजस में नजर आ रही है

■ भाजपा के इस गढ़ को ढहाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में टिकट चयन को लेकर भी बड़ी ही सतर्कता बरती जा रही है

इस जाति के मतदाता काफी अहमियत रखते हैं। जालोर में भाजपा से वर्तमान विधायक जोगेश्वर गर्ग का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस से इस बार भाजपा के इस गढ़ को ढहाने के लिए मजबूत दावेदार की तलाश कर रही है। लेकिन कांग्रेस से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, एनएसयूआई की छात्रा नेता सुष्मिता गर्ग को चुनाव मैदान में उतार सकती है। रामलाल मेघवाल को टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय

ताल ठोकने की तैयार कर चुके हैं। वही रामलाल मेघवाल ही गर्ग को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मेघवाल के राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने से आलाकमान के समक्ष उनकी छवि धूमिल जरूर हुई तथा ये ही उनको टिकट नहीं मिलने में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। लेकिन जालोर में कांग्रेस अधरक्षल में नजर आ रही है। ऐसे में एनवक्त पर कांग्रेस किसी नये चेहरे को चुनाव मैदान में उतर सकती है।

आहोर विधानसभा क्षेत्र में चौधरी

व पुरोहित समाज के मतदाताओं पर प्रत्याशी के हार-जीत का फेसला निर्भर करता है। आहोर में भाजपा के वर्तमान विधायक छगनसिंह राजपुरोहित विकास कार्य करवाने में सफल नहीं हुए। वहीं जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर आहोर क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में सफल जरूर हुए हैं। ऐसे में आहोर सीट वयोवृद्ध भगराज चौधरी के समय कांग्रेस की गढ़ रही है। भगराज के बाद कांग्रेस का कोई दमदार प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारने से लगातार तीन विधानसभा सीट भाजपा की झोली में जाती रही। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के इस गढ़ को तोड़ने के लिए इस बार विकास कार्य करवाये हैं। वही दमदार प्रत्याशी की तलाश कर रही हैं। भाजपा से वर्तमान विधायक छगनसिंह व पूर्व विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित के बीच टिकट

को लेकर घमासान चल रहा है।

ऐसे में दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो भाजपा तीरपे विकल्प के रूप में किसी नये चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है वहीं कांग्रेस के पास अभी तक मजबूत दावेदार नहीं है। सवाराम पटेल कांग्रेस से दो बार इस क्षेत्र से हार चुके हैं तथा इस बार कांग्रेस भाजपा के इस गढ़ को ढहाने के लिए मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस से पहले चर्चाए थी कि पुखराज पाराशर ने इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाये हैं तो चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन पाराशर सीएम के खास होने से चुनाव के दौरान पूरा कार्य देखने से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस किसी नये चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में उतार सकती है। आहोर में चौधरी व पुरोहित समाज के वोटों के बल पर नैया पार की जा सकती है।

फिरौती मांगने के आरोपी चूरु पुलिस के हथ्थे चढ़े

होटल संचालक पर फायरिंग कर फिरौती मांगने का मामला



फायरिंग कर फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया।

चूरु, (कासं)। हरियाणा के हिसार जिले में एक होटल संचालक पर फायरिंग कर फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमन सुरा पुत्र रतन सिंह जाट (22) निवासी थाना बरवाला जिला हिसार व राकेश उर्फ राजा पुत्र अजमेर विरनोई (25) निवासी थाना सदर हिसार रविवार देर रात गश्त कर रही तारानगर थाना पुलिस के हथ्थे चढ़ गये। जिन्हें शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया

कि वॉलेंट अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार बुटोलिया व सीओ जय प्रकाश बेनीवाल के सुपरविजन में रविवार देर रात एसएचओ नवनीत सिंह मय टीम के गश्त पर थे। इस दौरान संदिग्ध युवकों अमर सुरा व राजेश उर्फ राका को डिटेन कर शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी हिसार जिले में अपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों

आरोपियों से संबंधित थाना से आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर था। हिसार की सीआईए से मालूम किया तो उन्होंने दोनों का थाना सिविल लाइन हिसार के प्रकरण में 5 सितंबर से फरार होना बताया। आरोपियों ने सिविल लाइन इलाके में एक होटल संचालक पर हथियार से फायरिंग कर फिरौती मांगी थी। उसके बाद पुलिस के डर से फरार होकर चूरु आ गए। इस कार्रवाई में कान्टेबल हीरालाल की मुख्य भूमिका रही।

आर.एस.एस. व भाजपा को मैं कुछ नहीं समझता : डोटासरा

सुजानगढ़, (निर्सं)। आरएसएस व भाजपा को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। ये बयान एक बार फिर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने नवसृजित बैराम पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में सम्बोधित करते हुए कही। डोटासरा ने कहा कि इस बार भाजपा को साफ कर दूँगे। चूरु जिले में अब मैं घूस चुका हूँ। यहां से राठौड़ को चुनाव हरायेंगे। भीड़ देख गढ़गढ़ हुए डोटासरा ने भीड़ का वीडियो राजेन्द्र राठौड़ को भेजने का कहा। इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए किये गये महिला आरक्षण बिल पर डोटासरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल लाने वालों को पता नहीं है कि यह बिल धरातल पर कब लागू होगा।

भाजपा की परिवर्तन यात्राओं पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि उनकी सभाओं में जनता से ज्यादा भीड़ नेताओं की होती है। डोटासरा ने सरपंच

■ डोटासरा ने नवसृजित बैराम पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित किया

रामी देवी दुसाद व डॉ. रामेश्वर दुसाद द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि आचार संहिता लगने से पहले बैराम गांव की स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हो जायेगी। डोटासरा ने कहा कि बिना सरकार चुने ही भाजपा में दस मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि हमने अगर कार्य किये हैं तो जनता हमें फिर से सत्ता में लेके आयेगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रसाराम गोदारा, पूर्व जिला प्रमुख पंवारलाल पुजारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इन्द्रज

खीचड, विद्याधर बेनीवाल, गणेश ढाका, दीवान सिंह भानीसरिया, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष विकास सारण, डॉ. रामेश्वर दुसाद, पंचायत समिति सदस्य रामराम दुसाद, मनसुख गोदारा, महेन्द्र गोदारा, रूपाराम कर्वाण सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर आयोजक डॉ. रामेश्वर दुसाद द्वारा स्वागत किया गया।

डोटासरा के जन्मदिवस पर ग्रामीणों द्वारा डोटासरा से केक कटवाया गया। डोटासरा ने तलवार से केक काटा व ग्रामीणों द्वारा दी गयी बधाई पर आभार जताया। डोटासरा ने कहा कि पहली बार राजस्थान में किसान के बेटे को शिक्षा मंत्री बनाया गया। भाजपा ने वोटों के लिए अतिरिक्त कर केसरिया रांग कर दिया। वोटों के लिए चट्टी, बनिजान ने भी केसरिया रांग कर दिया। डोटासरा ने कहा कि इनसे वोट हासिल होने वाले नहीं हैं। वोटों के लिए जनता का दिल जीतना जरूरी है।

आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने की डीसीपी की मांग

अजमेर, (कासं)। दो वर्षों से शेष वंचित सीनियर संविदा आयुर्वेद डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को आयुर्वेद निदेशालय अजमेर पर अनिश्चित कालीन आमरण अनशन शुरू किया। डीपीसी की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से आयुर्वेद संविदा चिकित्सकों द्वारा धरना प्रदर्शन जिले बारा दिया जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद विभाग व राज्य सरकार ने अभी तक मांगों को पूरा करना तो दूर संज्ञान तक नहीं लिया है।

वंचित सीनियर संविदा आयुर्वेद डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. सुनील खारवाल, डॉ. देशराज डगुर

सहित अन्य ने बताया कि डीपीसी मांग सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले दो वर्षों से शेष वंचित सीनियर संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने मांग की कि आयुर्वेद विभाग (नियम 1973) के चिकित्सकों को वर्ष 2023 की सभी पेंडिंग डीपीसी एक साथ शीघ्र करवाकर विभाग में उपलब्ध करीब तीन सौ पदों को वर्तमान में भर्ती (02/2023) की प्रतीक्षा सूची में जोड़कर वंचित रहे चिकित्सकों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि आज तक सभी आयुर्वेद अधिकारी भर्ती से वंचित रहे

चिकित्सकों का स्थायीकरण न होने के कारण आगामी भर्ती में अधिकांश वंचित चिकित्सक उम्र की सीमा पार कर कर जायेंगे ऐसे में जीवन भर स्थायी नहीं हो पाएंगे। साथ ही पिछले कई वर्षों से अटकी पड़ी ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों की 272 पदों की डीपीसी भी शीघ्र करवा कर रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती की प्रतीक्षा सूची में जोड़कर वंचित आयुर्वेद को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी मांगों पर आयुर्वेद विभाग तथा सरकार द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में मजबूर होकर गांधी जयंती से आमरण अनशन शुरू किया है।

गुर्जर समाज जिला अजमेर की समाज को टिकट देने की मांग

अजमेर, (कासं)। चुनाव के मद्देनजर एमबीसी वर्ग गुर्जर समाज जिला अजमेर ने कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को पत्र प्रेषित कर अजमेर जिले में दो विधानसभा तथा एक लोकसभा सीट पर टिकट दिए जाने की मांग की है। गुर्जर समाज जिला अजमेर प्रवक्ता भगवानसिंह गुर्जर ने बताया कि सोमवार को संत-महंत, पंच पटेल गुर्जर समाज जिला अजमेर के विडियादास महाराज के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोश व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के

नाम का ज्ञापन प्रेषित किया प्रवक्ता भगवानसिंह ने बताया कि एमबीसी वर्ग की गुर्जर जाति की आबादी प्रदेश के 16 जिलों में निवास करती है। गुर्जर समाज जिला अजमेर के संत, महंत, पंच पटेल विडियादास महाराज ने कहा कि हर क्षेत्र में उपेक्षित होने की वजहा को लेकर गुर्जर समाज अजमेर ने एक राय होकर निश्चय किया है कि जो राजनीतिक दल गुर्जर समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए योग्य नेताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में कम से कम 2 सीटों पर और अजमेर लोकसभा सीट पर एक प्रत्यशी घोषित करेगा, उसी दल को जिला गुर्जर समाज पूरे जिले में एकतरफा सहयोग व समर्थन करेगा।

खान व्यवसायी से 25 लाख की अवैध वसूली की मांग

पाटन, (निर्सं)। खान मालिकों द्वारा 25 लाख की अवैध वसूली की मांग का प्रकरण थोई थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसआई सीताराम को दी है। वहीं धमकी भरे पत्र से क्षेत्र के अन्य खान मालिकों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

दर्ज प्रकरण में बताया कि नीमकाथाना के खान व्यवसायिक दौलतराम गोयल, महेंद्र गोयल की खान पर विगत रात्रि तीन लोग बाइक पर सवार होकर आए तथा खान पर काम करने वाले मकखन लाल के हाथ में एक लिखित कागज थमाते हुए कहने लगे कि तेरे क्रैसर मलिक दौलतराम गोयल व महेंद्र कुमार गोयल को कह देना कि खान पर कांटा तुलाई मशीन चालू करने से पहले संदीप उर्फ सुखा शूटर निवासी पीथमपुरी से संपर्क कर लें तथा 25 लाख रुपए फिरौती के रूप में हमें दे दे, नहीं तो तेरे मलिक को जान से खत्म कर देंगे। तेरे दोनों मालिकों को जान से हाथ धोना पड़ेगा तथा खान भी हाथ से निकल जाएगी। उक्त व्यक्ति जोर-जोर से चिल्लाते हुए गाली-गलौज भी करने लगे। मैंने खान में काम कर रहे पुंभेंद्र सिंह, छीतरमल, शायर धानका, बंसी खाती चौकीदार को बुलाया

■ एक व्यक्ति ने पिस्टल से खान पर काम करने वाले पर मारने की नियत से गोली चलाई

तथा गाली-गलौज नहीं करने के लिए कहा तो उक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने पेंट में छुपा कर रखी पिस्टल को निकाल कर मुझे जान से मारने की नियत से मेरी तरफ गोली चलाई। मैं तुरंत नीचे की तरफ बैठ गया जिससे पिस्टल से निकली हुई गोली मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, जिस कारण मेरी जान बच गई। तीनों बदमाश कह रहे थे पंचवीस लाख रुपए नहीं दोगे तो खान मलिक दौलत गोयल एवं महेंद्र गोयल को जान से मार दिया जाएगा। खान मालिकों द्वारा इस प्रकरण को थोई थाने में दर्ज करवाया है। क्षेत्र में पहले भी इस तरह की कई खबरें दातों घट चुकी हैं। मकखन लाल ने बताया कि मेरे को जो कागज दिया गया था उसमें संदीप गोयल को जान से मारने की नियत से गोली चलाई है, जो कागज मेरे पास है।

बाइक सहित आरोपी गिरफ्तार

मण्डावरी, (निर्सं)। मण्डावरी थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। थानाधिकारी धर्मेन्द्र मोघा ने बताया कि चरत लाल ने थाने पेश होकर बाइक चोर का मामला दर्ज करवाया था। जिस पर मण्डावरी थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चोरी की वारदातों को गम्भीरता से लेते हुए टीम का गठन किया। टीम ने

इलाका थाना क्षेत्र में चोरी करने वाली सक्रिय गिरोह का पर्दाफास करते हुए मुखबीर खास मामूर किया जाकर आसूचना संकलन कर आरोपी बिजेन्द्र को गिरफ्तार कर चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आरोपी विजेन्द्र सैनी को सोमवार दर्ज बाइकी स्थित अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया जहां उनके आदेशों पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

राज्य मंत्री अशोक चांदना के गृह क्षेत्र हिंडोली में नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण

अतिक्रमियों के आगे प्रशासन नतमस्तक, नोटिस देकर खानापूर्ति की

बून्दी, (निर्सं)। बूंदी जिले के मंत्री अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र हिंडोली में इन दिनों अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों ने राजनीतिक संरक्षण के चलते एनएच 12 पर स्थिति बेशकीमती पांच बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। जिससे क्षेत्रीय लोगों के कुएं, खेतों, मकानों, कराड खेड़ी, कालसी का बरडा, मोन्दोलिया का बरडा व छोटी फैक्ट्री जाने का रास्ता 30 फीट से सिकुड़ कर बंद सा हो गया है।

ग्रामीणों के अनुसार हिंडोली देव गुर्जर छात्रावास के सामने एन.एच 12 से होते हुए 30 फीट का आम रास्ता निकला हुआ है। दो दिन पहले अतिक्रमियों द्वारा आम रास्ते की जगह को बेचकर आम रास्ते पर जेसीबी से खाई लगावा दी व जमीन पर अतिक्रमण करते हुए सीमेंट के पिलर लगा दिये। जिससे 30 फीट का रास्ता सिकुड़ कर 12 फीट का रह गया। जिससे खेतों तक संसाधन ले जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालसी का झोपडा के ग्रामीणों ने 17 सितम्बर को उक्त अतिक्रमण की शिकायत को लकर उपखंड अधिकारी के ज्ञापन सौंपा था, जिस पर उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने 18 सितम्बर को पत्रांक 2308 जारी कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को उपयुक्त कार्रवाही के आदेश दिए थे। जिसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। केवल मात्र नोटिस देकर



हिंडोली में लोगों ने राजनीतिक संरक्षण के चलते बेशकीमती पांच बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर लिया।

खानापूर्ति कर ली है। जानकार लोगों की माने तो उपखंड कार्यालय के पास स्थित खसरा नंबर 6326/ 2867 जो कि करोड़ों रुपए की आबादी क्षेत्र की जमीन है, जो तरममीशुदा नगर पालिका के खाले की है। जहां पीछे कृषि भूमि एवं मजरा में आने जाने का आमरास्ता भी है। जिसको भी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर केवल 12 फीट का रख दिया गया है। जिस पर पंचायत समिति हिंडोली द्वारा मनरेगा कार्य के अंतर्गत प्रेवल का कार्य भी करवाया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायत तहसीलदार उपखंड अधिकारी व नगर पालिका ईओ को कई बार की गई। प्रदेश

के राज्य मंत्री अशोक चांदना का विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी प्रशासन इसे खाली कराने में असमर्थ दिखाई दे रहा है जिसका सीधा-सीधा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि अतिक्रमियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है उल्टा कार्रवाई करने वाले नगर पालिका ईओ को रातों-रात एपीओ कर दिया गया। कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा न्यायालय की शरण लेते हुए उक्त जमीन के मामले को लेकर न्यायालय अपील की गई है जो कि विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई मंगलवार को न्यायालय में होनी है।

क्षेत्रीय लोगों की माने तो अतिक्रमी प्रभावशाली लोग हैं और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिसके सत्यपन कराया जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके तथा सरकार को राजस्व का लाभ मिल सके व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पट्टे नियम विरुद्ध पाई जाएंगे। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि उक्त पत्र पट्टों का भौतिक सत्यापन कराया जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके तथा सरकार को राजस्व का लाभ मिल सके व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

■ अतिक्रमियों ने खाई लगाकर गांवों को जोड़ने वाले रास्ते को बंद किया

■ ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को रास्ता बहाल करने का ज्ञापन सौंपा

■ भूमाफियाओं से मिलीभगत कर पंचायत ने खाली भूखंड पर ही बना दिए पुश्तैनी आवास के पट्टे

पट्टे नियम विरुद्ध पाई जाएंगे। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि उक्त पत्र पट्टों का भौतिक सत्यापन कराया जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके तथा सरकार को राजस्व का लाभ मिल सके व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

थाने के पास नाथ समाज के व्यक्तियों द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर दर्जनों दुकानें बना ली हैं। वहीं देवनारायण छात्रावास के सामने भी अतिक्रमण कर दुकानें निर्मित करवाई जा चुकी हैं। इसी प्रकार अन्य लोगों द्वारा भी व्यावसायिक दुकानें बनाई गई हैं जिस पर प्रशासन आखें मूंद बैठा हुआ है। इन सभी स्थानों पर शिकायत करने के बाद केवल प्रशासन ने नोटिस देकर इतिश्री कर ली है। जिसका सीधा-सीधा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि सभी अतिक्रमियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

कुलदीप सिंह शेखावत उपखंड अधिकारी हिंडोली ने बताया कि जमीन नगर पालिका अधिकार क्षेत्र की है, इसका पूरा उत्तरदायित्व नगर पालिका का है भरे पास मामला आया था मैंने अंतरिम रूप से काम रुकवा दिया था तथा नगरपालिका ईओ को कार्रवाई के लिए आदेश भी जारी किया था। नगर पालिका अतिक्रमण को हटाने के लिए जाब्ता मांगेगा तो मैं जाब्ता उपलब्ध करा दूंगा।

राम सिंह गुर्जर, तहसीलदार हिंडोली ने बताया कि उक्त जमीन नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। ई.ओ. को इस पर कार्रवाई करने का अधिकार है। वहीं नाथ समाज के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों के मामले में जमीन रिकॉर्ड में एनएचआईई के नाम दर्ज हैं। मामले में जांच करा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इकबाल हत्याकाण्ड में चार गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी परकोटा स्थित सुभाष और रामगंज इलाके में शुक्रवार देर रात को हुए इकबाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक नाबालिग को भी निरूद्ध किया है। वहीं घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) भी गठित गई है।

पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि 29 सितम्बर को इकबाल पुत्र अब्दुल मजीद निवासी 2546

- मामले में एक नाबालिग निरूद्ध
- घटना के त्वरित अनुसंधान के लिये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित
- शान्ति समिति व सीएलजी की मिटिंग लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील



माणक चौक इलाके में जौहरी बाजार स्थित पुरोहित जी के कटले में हमले के खिलाफ पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता ने सोमवार को व्यापारियों के साथ थाने पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज करावाई है।

पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई

नमदगारों का मोहल्ला रामगंज बाजार की हत्या के संबंध में उसके भाई अलफेज मंसूरी ने सुभाष चौक थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया था। मामले की त्वरित जांच के लिये अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रेवतनदान के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध कैलाश चन्द्र विश्वा ने बताया कि इस हत्याकाण्ड में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है। वहीं आरोपी युवराज उर्फ राज करण्य पुत्र प्रमोद करण्य, शुभम मेहरा उर्फ गोलू पुत्र दैलत निवासी गंगापोल सुभाष चौक व दो अन्य आरोपियों को बापदाँ गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरूद्ध किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उधर, इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सोशल मिडिया सेल का भी गठन किया गया है।

डीसीपी नोर्थ राशि डोगरा ड्यूटी ने बताया कि सोमवार को जौरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों, शांति समिति व सीएलजी सदस्यों की मिटिंग पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम कैलाश चन्द्र विश्वा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय कुंवर रायूदीप व जिला जयपुर उक्त के पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त व सभी थानाधिकारी भी शामिल हुए। सभी आम जनता से साम्प्रदायिक सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की गयी। उधर, दूसरी ओर सुभाष चौक इलाके और रामगंज बाजार में सहित अन्य स्थानों पर आज भी पुलिस का जाप्ता तैनात रहा।

रीको में पेंशन के ऐरियर का भुगतान करने की मांग

जयपुर। रीको रिटायर्ड एम्पलाईज वेलफेयर एसोसियेशन (रीवा) की साधारण सभा की बैठक रविवार को रीको रोड हाउस, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक के बाद रीवा के प्रधान सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष जी. एस. शेखावत, महासचिव कृष्ण गोपाल सोपेरिया ने बताया कि रीको ने 30 सितम्बर तक लगभग 625 लम्बित पीपीओ के तहत 31 पीपीओ जारी कर, अधिशाषी निदेशक, अरुण गर्ग ने अपना आव्रसान पूर्ण किया है, इसके लिये सदस्यों ने गर्ग का आभार जताया और आशा की है कि शेष पीपीओ भी शीघ्र जारी करेंगे।

बाइक सवारों के बीच झगड़े की आड़ में साम्प्रदायिक हिंसा का विरोध

जयपुर। शहर के गंगापोल क्षेत्र में 29 अक्टूबर को हुई दुर्घटना को साम्प्रदायिक रंग देने के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को प्रातः 10 बजे बड़ी चौपड़ पर धरना दिया जाएगा।

समिति के राजकुमार शर्मा का कहना है कि बीच बचाव के दौरान आत्मरक्षा में हुई दुर्घटना को माँव लिंगिका का नाम देकर हिन्दू परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। घटना की आड़ में समुदाय विशेष की हिंसक भीड़ द्वारा शहर में की जा रही लूटपाट और तोड़फोड़ के विरोध में यह महाधरना दिया जाएगा।

फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि इस झगड़े के दौरान एक युवक ने आत्मरक्षा में हमलावर से सरिया खीन लिया और यह दुर्घटना घट गई। इसी क्रम में अगले दिन समुदाय विशेष की हिंसक भीड़ ने सड़कों पर उतर कर लूटपाट शुरू कर दी। समिति का आरोप है कि स्थानीय विधायकों का प्रशासन पर लगातार दबाव होने के चलते पुलिस ऐसी घटनाओं में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाती। इसीलिए इन घटनाओं के प्रति विरोध जताने के लिए समिति बुधवार को बड़ी चौपड़ पर धरना देगी।

मशहूर गीतकार शैलेन्द्र के नगमों से श्रोता आत्म-विभोर हुए

जयपुर, (का.सं.)। जवाहर कला केंद्र का रंगायन सभागार आज शाम हिंदी सिने जगत के मशहूर गीतकार शैलेन्द्र के भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी नगमों का साक्षी बना। सुपर 60 क्लब से जुड़े गायक-गायिकाओं की प्रत्येक प्रस्तुति के बाद सभागार में श्रोताओं की तालियों की गूँज देर तक सुनाई दी। इस महान गीतकार की जन्मश्रांति के मौके पर देवरञ्जनी म्यूजिक स्कूल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम "आवारा हूँ" में प्रस्तुत गीत सीधे श्रोताओं के दिल में उतरते चले गए।

इस यादगार कार्यक्रम की शुरुआत स्व. शैलेन्द्र की अमला मजूमदार, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन, मशहूर संगीतकार मदन मोहन की सुपुत्री संगीता गुप्ता और बॉलीवुड स्तम्भकार पवन झा द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद कार्यक्रम की संयोजक और देवरञ्जनी म्यूजिक स्कूल की निदेशक डॉ. सारिता द्विवेदी ने चारों अतिथियों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में विशेष सहयोग करने वाले अनिल बजाज, आर्युष कल्ला और सुधीर माथुर को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया। तीन घंटे चले इस कार्यक्रम का प्रारम्भ शीर्षक गीत



जवाहर कला केंद्र का रंगायन सभागार में सोमवार शाम को सुपर 60 क्लब से जुड़े गायक-गायिकाओं ने हिंदी सिने जगत के मशहूर गीतकार शैलेन्द्र के नगमों की प्रस्तुति दी।

"आवारा हूँ" से हुआ और अंत में "जीना यहाँ मरना यहाँ" पेश किया गया। इस दरमियान जहाँ मैं जाती हूँ, गाता रहे मेरा दिल, बोल रहे कटपुतली, मेरे मन की गंगा,

कालजयी और अमर गीत प्रस्तुत किये गए। शैलेन्द्र के कुछ सुप्रसिद्ध गीतों को एक अलग अंदाज में पेश किया गया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

कालजयी और अमर गीत प्रस्तुत किये गए। शैलेन्द्र के कुछ सुप्रसिद्ध गीतों को एक अलग अंदाज में पेश किया गया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

आवासन कर्मचारी संघ का अनशन आज

जयपुर (कासं)। राजस्थान आवासन बोर्ड, कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दशरथ कुमार एवं प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में 11 कर्मचारी 3 अक्टूबर से अनशन पर बैठेंगे। संघर्ष समिति के संयोजक रमेश चन्द्र शर्मा एवं संयुक्त महासचिव गोविन्द नाटाणी ने बताया कि 3 अक्टूबर से प्रदेश स्तर पर मुख्यालय पर 11 पदाधिकारियों द्वारा क्रमिक अनशन शुरू किया जायेगा। महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मण्डल से गलत तरीके से 1000 हजार करोड़ रुपये लिये जा रहे हैं, वर्तमान में मण्डल की 2700 करोड़ रुपये देनदारियाँ हैं, और मण्डल कोष में मात्र 1500 करोड़ रुपये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को विगत दिनों में जापन दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये लिए जा चुके हैं। कई करोड़ रुपये की छूट दी जा चुकी है। करोड़ों रूपयों की जमीन पर सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। मण्डल की भूमि अवाचित के प्रकरणों पर सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। परन्तु सरकार अपने अनैतिकपूर्ण निणयों पूर्ण करने पर अडिग है जिसका मण्डल कर्मचारियों द्वारा जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ अध्यक्ष दशरथ कुमार ने प्रशासन एवं राज्य सरकार से आवासन बोर्ड को राजकीय विभाग करने की मांग करते हुये कहा कि यदि राज्य सरकार मण्डल कार्मिकों को राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित कर दे ताकि कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की गारंटी रहे।

व्यापारी से 28 लाख रुपए ठगे

जयपुर (कासं)। विद्याधर नगर थाना इलाके में एक शांतिर युवती ने व्यापारी हनीट्रेप में फंसाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। युवती से परेशान होकर व्यापारी ने पिता से सहित तीन जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लाख रुपए ठगे

कुछ दिन बाद पीड़ित के पैर का ऑपरेशन हुआ। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान शिवांगी ने काफी पैसों का गबन किया। पीड़ित ने शिवांगी को नौकरी से हटाने के लिए कहा तो शिवांगी ने काफी मांगते हुये काम पर लौट आई। शिवांगी ने कारोबारी को खाने में नशे की चीज मिलाकर दी और नशे की हालत में आपत्तिजनक फोटो खींच कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 28 लाख रुपए हड़प लिया। पैसे लेने के बाद भी 20 लाख रुपए की और डिमांड कर दी। रोज-रोज की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित ने विद्याधर नगर थाने पहुँचकर महिला के विरूद्ध मामला दर्ज कराया।

पुरोहितजी के कटले में व्यापारियों से मिले सांसद बोहरा

जयपुर। बीते दिनों जौहरी बाजार स्थित पुरोहितजी के कटले में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा लूटपाट एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना को लेकर जयपुर सांसद रामचंकर बोहरा ने कटले के व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सांसद बोहरा ने कहा कि इस तरह की घटना जयपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

इससे शहर का शांतिपूर्ण माहौल एवं सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है। अब शहर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे टाइम पर इस तरह की घटना से जयपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। जिससे स्थानीय व्यापारियों का नुकसान होगा। सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई कर इस घटना में लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए।

सांसद बोहरा ने मौके पर पुलिस अधिकारियों से बात कर व्यापारियों के मुकदमे जल्द से जल्द दर्ज करने और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

कार्मिकों को मिलेगी शोषण से मुक्ति

जयपुर। हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है। इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी कम्पनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय किया गया। रेस्कको की तबर्ष पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कम्पनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री जयपुर में घर ले ले, ताकि आने-जाने का समय और खर्चा बचे : खेड़ा

जयपुर, (का.प्र.)। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10वाँ बार राजस्थान के दौर पर आये तथा 5 अक्टूबर को राजस्थान का 11वाँ दौरा करेंगे, उन्हें प्रदेश में ही एक घर ले लेना चाहिये, ताकि बार-बार आने जाने में हो रहे सरकारी खर्च का बोझ जनता पर ना पड़े। प्रधानमंत्री यदि सत्य बोलने का प्रण लें तो यह खर्चा राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रहण करने के लिये तैयार है।

कांग्रेस मीडिया एवं कम्प्यूटिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने जयपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जाल में फंस गये तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू जनकल्याणकारी योजनाओं को अच्छा बताकर जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है तथा अच्छी योजनाओं के बलबूते पर वोट भी राजस्थान की जनता कांग्रेस को ही दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर बात करने का साहस किया है लेकिन भाजपा के ही वरिष्ठतम विधायक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुनराम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस की सरकार अथवा कांग्रेस के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये।

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

जयपुर, (का.सं.)। महिला उन्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने शादी के दो महीने बाद ही दहेज के लिए पत्नी हत्या करने वाले प्रागपुरा निवासी अभियुक्त पति मुखराम यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी कुत्सित मानसिकता वाला अभियुक्त किसी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने बताया कि मृतका विनीता की मां पुष्पा देवी ने महेश नगर पुलिस थाने में अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई

- शादी के दो माह बाद ही दहेज के लिये पत्नी की हत्या का मामला
- अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

थी। इसमें कहा कि उसकी बेटी की शादी मुखराम के साथ 3 नवम्बर, 2014 को हुई थी, लेकिन शादी के तीन दिन बाद ही ससुराल वालों ने उसकी बेटी पर कम दहेज लाने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल वालों ने उससे कार देने की मांग की। वहीं पिता के

रिटायरमेंट के समय भी जयपुर में मकान लेने के लिए पांच लाख रुपए मांगे और नहीं देने पर मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी के चलते 28 जनवरी 2015 को उसकी बेटी की महेश नगर थाना इलाके में किराए के मकान में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने विनीता की मौत गला दबाने के कारण दम घुटने से होना बताया। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पति मुखराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त पति को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई।



राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजभवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मिश्र ने इन दोनों विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जन जन की सत्य, अहिंसा और न्याय के साथ ईमानदारी से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निर्वहन के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री का प्रदेशाध्यक्ष जोशी को बार बार तवज्जो देना बना चर्चा का विषय

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा बार-बार इतनी तवज्जो देने की चर्चाएं आजकल अक्सर सुनाई पड़ रही हैं। जयपुर में स्थित दादिया की सभा के बाद भाजपा मुख्यालय में ये अक्सर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले जयपुर स्थित दादिया में सभा के दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को प्रधानमंत्री मोदी ने खुली जीप में बैठा कर लाए थे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री ने सांवलियाजी में हेलीपैड से जोशी को अपने साथ में कार में बैठाकर सांवलिया सेट मंदिर में पहुंचे। सभा स्थल तक साथ बैठाकर ले गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सीपी जोशी मेवाड़ और राजस्थान के विकास के मुद्दों को संसद में जोर शोर से उठाते हैं और आज मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान में गूँज रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीपी जोशी को साथ रखकर साफ मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। वे हमेशा से ही नेता को नहीं संगठन को तवज्जो देते हैं। किसी अन्य नेता को साथ लेकर चलने में प्रदेश में चुनौती समय में गुटबाजी बढ़ने की संभावना रहती है जिसके लिए वे संगठन को ही तवज्जो देते हैं।

बीस आई.पी.एस. अधिकारियों के तबादले

जयपुर। राज्य सरकार ने सोमवार रात एक बार फिर पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें दो पुलिस उपमहानिरीक्षक और 6 पुलिस अधीक्षक को भी बदला है।

- तबादलों में दो पुलिस उपमहानिरीक्षक और 6 पुलिस अधीक्षक शामिल

अवना को पुलिस अधीक्षक जौआरी अजमेर, आदर्श सिधू को कर्माडेट 12वीं बटालियन, आरएएससी, नई दिल्ली, दो पुलिस उपमहानिरीक्षक आर्म्ड बटालियन जयपुर और ओमप्रकाश को पुलिस उपमहानिरीक्षक एसडीआरएफ जयपुर के पद पर लगाया है। इसके अलावा राजकुमार गुप्ता को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा जयपुर, आलोक श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर, पूजा

अधीक्षक साहब क्राइम जयपुर, राजेश कुमार यादव को पुलिस अधीक्षक गंगापुरसिटी, हनुमान प्रसाद मीणा को पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर कमिश्नरीट, राजेश कांठट को पुलिस उपायुक्त क्राइम जयपुर पुलिस कमिश्नरीट, नरेन्द्र सिंह मीणा को पुलिस अधीक्षक दूदू, रमेश मोर्य को पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जोधपुर कमिश्नरीट, राजेन्द्र कुमार मीणा को पुलिस उपायुक्त क्राइम जोधपुर कमिश्नरीट, सुशील कुमार को कर्माडेट पांचवीं बटालियन आरएससी जयपुर और सुजीत शंकर का सहायक पुलिस अधीक्षक चौमू जयपुर ग्रामीण के पद पर तबादला किया गया है।

मंदिर में चाकू मारकर चौकीदार की हत्या

जयपुर। बनीपार्क में एक मंदिर परिसर में अज्ञात लोगों ने चौकीदार को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लहलुहान हालत में चौकीदार किसी तरह रोड तक पहुंचा और राहगीरों को चाकू लगने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचित कर लोगों ने चौकीदार को गंभीर हालत में सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने सर्वाई मानसिंह अस्पताल रैंफर कर दिया गया। जहां एस्पएएस अस्पताल में चौकीदार ने सोमवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल हमलावर का पुलिस सुराग नहीं जुटा पाई है। हमलावर को शिनाख्क के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

- बनीपार्क क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना
- हमलावर ने चाकू से गला काटकर गाई को लहलुहान कर दिया था

धारदार हथियार से हमला कर उसका गला काट दिया। परिचितों ने उसे बनीपार्क सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। जहां गंभीर हालत में उसे सर्वाई मानसिंह अस्पताल रैंफर कर दिया गया। जहां सर्वाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवर्जन के सुपुर्द कर दिया गया है। परिवार के लोग शव लेकर आगरा रवाना हो गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि रविवार रात कोई शख्स पार्क में बेंच पर सो रहा था। जहां चौकीदार सुनील ठाकुर ने उसे टोका तो उस शख्स ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका गला काट

दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर हमलावर को शिनाख्क में जुटी है। इसके साथ ही एफएएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पार्षद रवि प्रकाश सैनी व अन्य लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने हमलावर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके अलावा भाजपा पूर्व विधायक अरुण चतुर्वेदी ने भी इस घटना को लेकर जोर जताया और पुलिस से इस वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग की है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर उ अंतोलन की चेतावनी दी। वहीं मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। बनीपार्क थानाधिकारी महेश चंद ने बताया कि चौकीदार पर मंदिर परिसर में हमले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो खून ही खून फैला नजर आया। पुलिस ने एफएएसएल टीम को मौके पर बुला कर सबूत जुटाए। एफएएसएल जांच के बाद मंदिर परिसर में फैले खून को साफ कर दिया है।

सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। शास्त्री नगर इलाके में रविवार रात हंगामा करने और साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले युवक रामपुत्र उर्फ अब्दुला पुत्र रामलाल शेख (35) निवासी खान जहांपुर (उत्तरप्रदेश) को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने बताया कि फसीउद्दीन निवासी रामगंज बाजार जयपुर ने लिखित शिकायत दी थी कि रविवार को शास्त्री नगर स्थित मैरिज गार्डन आरसी सेन्टर में विवाह के रिसेप्शन था। रात करीब साढ़े 10 बजे एक व्यक्ति आया और उनसे धार्मिक किताब खीनकर फाड़ दी और कहा कि यह किताब किसी काम की नहीं है। युवक के इस कृत्य से इस्लाम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता और मौके पर उपजे तनाव को देखते हुए मौके पर भारी जाप्ता तैनात किया। उधर समुदाय विशेष के लोगों ने युवक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया था। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त जात्ता मौके पर बुलाया। सोमवार को पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया।

डिग्गी में संत की हुई निर्मम हत्या का एक महिने बाद भी नहीं हुआ खुलासा

पदभार संभाल कर पुलिस उपाधीक्षक ने भूरिया आश्रम का जायजा लिया

मालपुरा, (निर्सं)। धर्म नगरी डिग्गी के भूरिया महादेव आश्रम में 93 वर्षीय संत सियाराम बाबा की 29 अगस्त की रात्रि को हुई निर्मम हत्या को 34 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन संत के हत्यारों का

- 29 अगस्त की रात्रि को हुई थी संत की निर्मम हत्या
- पुलिस के हाथ खाली, आश्रम में रखी हुई है संत की अस्थियां

सुराग लगा गिरफ्तार करने में सफल नहीं होने से संत समाज व सनातन धर्म के लोगों में गहरा आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभालते ही संत सियाराम बाबा की

हुई निर्मम हत्या की फाईल को हाथ में ले डिग्गी पहुंचकर भूरिया महादेव आश्रम व घटनास्थल सहित आसपास की 200 मिटर सीमा का बारीकी से मौका निरीक्षण कर जायजा लिया।

धार्मिक तीर्थस्थल पर 93 वर्षीय संत की रात के अंधेरे में आश्रम पर निर्मम हत्या करने तथा संत समाज द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी होने के बाद ही संत समाज की परम्पराओं के अनुरूप संत की अस्थियों को गंगाजी में विसर्जित करने व संत भंडारे का आयोजन करने की घोषणा के बाद अजमेर रैज आईजी लता मनोज कुमार ने डिग्गी पहुंच घटनास्थल का जायजा ले एसपी राजीव राज वर्मा को मामले में निष्पक्ष व त्वरित जांच एवं कार्यवाही के निर्देश देने के बावजूद 34 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा व हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालियां निशान लगा रहा है।



पुलिस उपाधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने डिग्गी के भूरिया महादेव आश्रम का जायजा लिया।

मौत पर मुआवजे की मांग पर रास्ता रोका, केस दर्ज

जोधपुर, (कासं)। शहर के जुनी मंडी स्थित गंगारामजी के मंदिर में नंदोत्सव के समय हुए हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर एमजीएच मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करने और रास्ता रोकने पर पुलिस ने भाजपा नेताओं, परिजनों, स्वर्णकार समाज के लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है। सरदारपुरा थाने में इस बाबत केस दर्ज हुआ है।

सरदारपुरा थाने के एसआई दीपलाल के अनुसार 30 सितंबर की शाम से देर रात्रि तक भाजपा नेता अतुल

भंसाली, राजेन्द्र सोनी, जनक सोनी, शिव कुमार सोनी के साथ दिलीप सोनी, नरेन्द्र सोनी, प्रेम नागौरी, दत्तु सोनी, शिवप्रकाश सोनी, निर्मल सोनी, किन्कराम सोनी, मोहन महामंजी सोनी समाज, भोजराज सोनी अध्यक्ष समाज संगठन, जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार रात 8 सितंबर को भीती शहर के गंगाराम जी मंदिर में रात में नंदोत्सव कार्यक्रम हादसे में एक युवक कैलाश सोनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी एमजीएच में 21 दिन बाद उपचार के बीच मौत हो

गई थी। इस पर परिजन, समाज के लोगों सहित जनप्रतिनिधियों की तरफ से मुआवजा राशि और अन्य मांगों को लेकर 30 सितंबर को एमजीएच मोर्चरी के सामने सड़क पर जाम लगाकर रास्ता रोका गया था। जबकि राज्य सरकार की तरफ से हाल में एक विधेयक लागू किया गया था कि शिव का सम्मान करना होगा। उसको लेकर कोई रास्ता रोकने या उपद्रव की मनाही थी, अन्यथा कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मगर उक्त लोगों द्वारा शिव का सम्मान नहीं किया गया और रास्ता रोककर प्रदर्शन करने के साथ जाम लगाया गया।

वाटरवर्क्स की टंकी पर चढ़े मृतक बालिका के परिजन

हनुमानगढ़, (निर्सं)। संगरिया के गांव नगराना राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र की डिग्गी में गिरने से चार वर्षीय बच्ची हरमन की हुई मौत के मामले में नाराज परिजन शाम छह बजे गांव के वाटरवर्क्स की टंकी पर चढ़ गए। वे लोग विद्यालय स्टाफ की लापरवाही को हादसे का कारण बता रहे हैं। उन्होंने यहां माहटद पांचों कर्मियों प्रधानाध्यापिका सहित दो अध्यापिकाओं व आंगनबाड़ी प्रतिनिधियों को निलम्बित करने सहित परिवार में एक सदस्य को सरकारी नियुक्ति तथा परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई है। टंकी के ऊपर चढ़ ने वालों में मृत बच्ची हरमन के चाचा आदराम, सोनु, चुन्रीलाल, सुरेश, सदीप कुमार एवं पृथ्वीराज शामिल हैं। गांव में टंकी पर चढ़ने की खबर फैलते ही भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद विनोद पूनिया, रामसिंह चहल, दलीप छिपा, सुनील तिवाड़ी, रुपराम, फूसाराम

विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र की डिग्गी में गिरने से बच्ची की मौत का मामला

सहित अन्य लोगों ने छोटी सी बच्ची की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। शांति व कानून व्यवस्था के लिए एसआई लक्ष्मणसिंह, एसआई वेदप्रकाश, कांटेबल रिंकू, रमेश, सुखवीर, मनीष, कुष्णादेवी पहुंचे लेकिन कोई अधिकारी मौके पर सम्झौदा करने या बात सुनने के लिए नहीं पहुंचा। जबकि परिजन जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर ग्रामीण तथा बच्ची के परिजन मौजूद हैं। पंचायत समिति के पूर्व डायरेक्टर भारीश मेघवाल ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी में बच्चे खुलेआम बरामदे में घूम रहे हैं। मौजूद विद्यालय स्टाफ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

11 बजे ही चली गई। बच्चों की हाजिरी भी नहीं लगाई। आरोप लगाया कि तीनों शिक्षकों ने छुट्टी तक ले ली। प्रधानाध्यापिका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, ऐसे में हाजिरी लगाकर चली जाती हैं। स्टाफ के कम्पे से महज पांच फीट दूर डिग्गी है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरमन के पिता वार्ड पांच नगराना निवासी वीरपाल नायक ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी हरमन (4) राजकीय प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी में पढ़ने जाती थी। बेटा करण (6) इसी स्कूल में पढ़ता है। रोज की तरह स्कूल गई थी। जहां करीब 11 बजे आंगनबाड़ी में खेल रही थी। यहां बनी पानी की डिग्गी के अंदर गिरने से मौत हो गई। आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी में बच्चों की कोई देखभाल नहीं है। डिग्गी पर डूबकर के ताला नहीं लगा था। केंद्र बंद होने का समय लगभग एक बजे तक है लेकिन वहां के टीचर जब

उन्का मन करता है तब ताला लगाकर अपने घर चले जाते हैं। आंगनबाड़ी के अंदर टंडे पानी के वाटरकुलर को कम्पे के अंदर ताला लगाकर रखा हुआ है। जबकि बच्चों को पीने के लिए टंडा पानी तक नहीं मिलता।

परिजनों के साथ प्रशासन की हुई वार्ता के बाद रात करीब नौ टंकी से परिजन नीचे उतर आए। लिखित में हुए समझौते के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हीरा देवी को हटाते हुए विद्यालय के तीन शिक्षकों रतन दीप, नीलम, शिव सैन्धा का पद स्थापन हनुमानगढ़ कर दिया गया। उन्हें 16 सीपीए को नोटिस देने, परिजनों के बयान के बाद पौजदारि मामला दर्ज कर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने, चिरंजीवी बिम्बा योजना के तहत पांच लाख की सहायता दिलवाने सहित परिवार के एक सदस्य को आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति दिलवाने पर सहमति बनी।

नहर में नहाने गया बच्चा गिरा, दिल के पास घुसी कांच की बोतल

बीकानेर, (कासं)। खाजूवाला में नहर में बच्चों के साथ अटखैलियां करता बच्चा गिर पड़ा, जिससे उसके दिल के पास कांच की बोतल घुस गई। कांच की बोतल से घाव हो गया और उसकी एक आंत बाहर निकल गई। परिजन उसे खाजूवाला सीएचसी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद पीबीएम अस्पताल रफेर कर दिया। पीबीएम के

चिकित्सकों ने देर रात को ही ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। खाजूवाला से दो किलोमीटर दूर बीकानेर रोड पर जयसिंह का चार वर्षीय बेटा पुष्पेन्द्र सिंह दो-तीन बच्चों के साथ माइनर (नहर) में नहारे उतरा। नहर में अटखैलियां करते समय पुष्पेन्द्र गिर पड़ा। नहर में इस कांच की बोतल पर गिर पड़ा, जिससे उसके दिल के नीचे

घाव हो गया और उसकी एक आंत बाहर निकल गई। परिजन उसे खाजूवाला सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर पीबीएम अस्पताल रफेर कर दिया। परिजन ने पीबीएम में समाजसेवी हरीकिशन सिंह राहपुरीहलित से संपर्क किया। समाजसेवी ने बच्चे के लिए रक्त की व्यवस्था कराई। बच्चे को परिजन

पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचे। यहां सीएमओ डॉ. एलके कपिल ने बच्चे की कंडीशन देखकर सर्जरी के चिकित्सकों को कॉल कर बुलाया। देर रात को सर्जरी के डॉ. रामशरण व उनकी टीम ने बच्चे की आंत का ऑपरेशन किया। बाद में बच्चे को सुपर स्पेशियलिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चे की हालत में सुधार है।

वाहन चोर गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, पुलिस उप अधीक्षक चांदमल सिगायीया के निर्देश पर हाथीपोल थानाधिकारी लच्छीराम टेलर मय टीम ने तलाशी अभियान के दौरान दुपहिया वाहन चोरी मामले में शांति आरोपी प्रेमा उर्फ प्रेमचंद पुत्र रामा बडगोटा निवासी शिवपुरा झाड़ोला को स्वरूपसागर रोड से चोरी की बाइक व तलवार सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में प्रेमा ने प्रतापनगर, सविना पुलिस थानाक्षेत्र में दो बाइक चोरी करने की वारदात करना स्वीकार किया है।

वनकर्मी के साथ मारपीट कर नकदी लूटी

उदयपुर, (कासं)। पुरोहित तालाब पर तैनात वनकर्मी के साथ मारपीट कर नकदी लूट ले जाने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पौडित किशन पुत्र भानु कुमार निवासी बोरों का गुडा अंबेरी ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि 1 अक्टूबर को पुरोहित तालाब पर घुमने आए बदमाशों ने गाड़ी हटाने की बात को लेकर कहासुनी होने पर मेरे साथ मारपीट की तथा नाके में आकर गल्ले से 11 हजार 600 रुपये नकदी लूट ले गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

तस्कर को 12 और सप्लायर को दस साल की जेल

आरोपी के पास से 600 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे

हनुमानगढ़, (निर्सं)। जिले के रावतसर में अपर जिला एवं सत्र जज राजेंद्र चौधरी ने नशीले कैप्सूल रखने के प्रकरण में आरोपी तस्कर लेखाराम को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सप्लायर परमजीत को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुमाना जमा नहीं कराने पर आरोपियों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार स्थानीय पुलिस थाना के एसआई रामकरण ने 1 सितंबर 2020 शाम के पौने पांच बजे खोड़ा मार्ग पर गश्त के दौरान 24 डीडब्लूडी पुलिसिया के पास एक व्यक्ति को सफेद रंग का थैला उठाए देखा जो पुलिस को देख कर खेतों में छिपने का प्रयास कर रहा था। शक होने पर उसे काबू कर देखा तो उसके पास रखे सफेद रंग के थैले में 600 नशीले कैप्सूल पारबोइन स्प्रास बरामद हुए, जिनके परिवहन अथवा रखने बाबत आरोपी के पास कोई प्रेवेंड अनुज्ञा पत्र या परमिट नहीं था। पूछताछ में उसने नशीले कैप्सूल आरोपी परमजीत से लेना बताया। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की

जुर्माना नहीं चुकाने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

तरफ से कोर्ट में 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया और 41 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। पुलिस द्वारा बरामद कैप्सूल के जल्दी प्रपत्र पर अंकित विवरण व एफएसएल रिपोर्ट में दर्ज विवरण समान मिले। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे राजेंद्र चौधरी ने बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पेरेवी अपर लोक अभियोजक महेंद्र जैन ने को।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अधिकांशतः समुग्र के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते परंतु इस मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत आरोपियों की कॉल डिटेल्स से सामने आया कि 2 दिन पूर्व से बरामदगी तक आरोपियों के बीच लगातार फोन पर बातें हुई हैं। एडीजे राजेंद्र चौधरी ने अपने निर्णय में लिखा कि आरोपियों के मध्य लगातार मोबाइल फोन से सम्पर्क रहा है। साथ ही बचाव पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि बातों

की विषय वस्तु भिन्न थी। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील कि सिम अन्य व्यक्ति के नाम की है, को भी खारिज करते हुए लिखा कि सामान्यतः आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी दूसरे के नाम से सिम लेते हैं।

अवैध शराब जब्त

उदयपुर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रियंका रुच्येश्वरी, पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वरलाल के निर्देश पारनवा थानाधिकारी उमेशचन्द्र के नेतृत्व में गठित दल ने अम्बसा में नाकजबदी के दौरान ककुआराम पुत्र लालु डामोर निवासी छाली बोकड़ा पारनवा को रोकरकर तलाशी ली तो उसकी बाइक पर बोरे में 90 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुई। पूछताछ में संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर शराब व बाइक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी दौरान पुलिस दल ने गुराड नदी पुलिया पर उत्पात मचाते पुनाराम पुत्र फुलाराम निवासी सुलाव माण्डवा व मौडालाल पुत्र फताजी निवासी सुलाव को शांति भंग में गिरफ्तार किया।

रेलवे ने से नया टाईम टेबल जारी किया

कोटा मंडल से प्रारंभ एवं टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव

कोटा, (निर्सं)। रेलवे ने एक अक्टूबर से प्रभावशील नई समय-सारणी जारी कर दी है। इसी के अन्तर्गत रेल परिचालन को सुचारू रूप से संचालित करने एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा रेल मंडल से प्रारंभ एवं टर्मिनेट होने वाली गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है। नई रेलवे समय सारणी के अनुसार कोटा मंडल के ओरजिनेटिव/डिस्ट्रिक्ट सॉर्टिंग पर कई रेलगाड़ियों की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेलवे पूछताछ एवं

एनटीईएस/139 से जानकारी प्राप्त करके ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। समय में बदलाव ट्रेनों का विवरण :- रेलगाड़ियों के प्रस्थान समय में बदलाव-19811 कोटा-इटावा एक्सप्रेस ट्रेन- (पूर्व समय रात्रि 23.50 बजे) अब परिवर्तित समय मध्य रात्रि 00.10 बजे रवाना होगी। 19807 कोटा-हिसार एक्सप्रेस ट्रेन- (पूर्व समय रात्रि 23.45 बजे) अब प्रस्थान करेगी। 19813 कोटा-हिसार एक्सप्रेस ट्रेन- (पूर्व समय रात्रि 23.50 बजे) अब परिवर्तित समय रात्रि 23.45 बजे रवाना होगी।

19104 कोटा-रतलाम एक्सप्रेस ट्रेन- (पूर्व समय दोपहर 13.40 बजे) अब परिवर्तित समय दोपहर 13.30 बजे रवाना होगी। रेलगाड़ियों के टर्मिनेट समय में बदलाव-20452 नई दिल्ली-सोमरिया एक्सप्रेस ट्रेन-पूर्व समय दोपहर 13.25 बजे और अब परिवर्तित समय दोपहर 13.30 बजे। 19819 वडोदरा-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन- पूर्व समय रात्रि 21.35 बजे और अब परिवर्तित समय रात्रि 21.30 बजे। 19110 मथुरा-कोटा मेमू एक्सप्रेस ट्रेन-पूर्व समय 13.30 बजे और अब परिवर्तित समय 13.20 बजे है।

‘महिला आरक्षण पर केन्द्र ने जनता को गुमराह किया’ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैफ अली नकवी अजमेर आये

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैफ अली नकवी ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव एवं राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल राजनीतिक एजेंडा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सैफ अली नकवी आज अजमेर प्रवास के दौरान सॉर्टिंग हाउस में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महिला आरक्षण बिल देश में अविबल लागू करना चाहिए। जनगणना और परिसीमन के बहाने वह बिल को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है और राजस्थान के सभी 25 सांसद मूकदर्शक बने हुए हैं। भारतीय

जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आम जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण राजस्थान देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉडल के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और हम दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा प्लॉप शो साबित हुआ है। परिवर्तन यात्रा में भाजपा को आम समर्थन नहीं मिल रहा था केवल भाजपा के कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि कांग्रेस सरकार के विरोध में भ्रामक प्रचार प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश की जनता अब जागरूक हो गई है और आने वाले चुनाव में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि महंगाई राहत शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को जागरूक किया जा रहा है। शिविर में गरीब वर्ग को महंगाई से राहत मिली है। इससे भारतीय जनता पार्टी हैरान और परेशान है और बौखलाहट में अन्नगल बयानबाजी कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता नकवी ने कहा कि हम जो कहते हैं वह करते हैं जबकि भाजपा केवल जुमलेबाजी कर आमजन को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को चार बहुमत मिलेगा और मुख्यमंत्री का भयन विधासक दल की बैठक में किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ती कांग्रेस की गुटबाजी पर उन्होंने कहा कि हर परिणाम में छोटे-मोटे बदल होते रहते हैं लेकिन हम सब पांचों उंगलियां बनकर एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं जबकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में

अंतर्कलह चरम सीमा पर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के कई हेरफेर घूम रहे हैं और आए दिन सिर फुटोबल हो रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनगर ने आरोप लगाया कि अजमेर जिले में सांसद, दोनों विधायक और नगर निगम अजमेर में भाजपा का बोर्ड है उसके बावजूद अजमेर में केंद्रीय योजनाओं का समुचित लाभ अजमेर की जनता को नहीं मिल रहा है जो कि निंदनीय है जबकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विगत 4 साल से अधिक समय से कांग्रेस के अभूतपूर्व सफल कार्यकाल से बौखलाहट में है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राओं में खाली कुर्सियों से साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हार्सिएर पर आ गई है और राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एव पूर्व

विधायक डॉ. राजकुमार जयपाल, पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रत्नवाल, हेमंत भाटी, सुनील लारा अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिवकुमार बंसल उपस्थित थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता नकवी के अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने माला एवं साफा बनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन जिला सदस्य बोर्ड के सदस्य आरिफ हुसैन नरेश सत्यवाना, मोहित मल्होत्रा अरशद ईसाक, सोना धनवानी, मनीष सेन, डॉ. मंसूर अली, आलोक गुप्ता, कशिश बायला, रोशन प्रकाश, जुनेद पटान, चतुर्भुष शर्मा, जाहद खान, मजहर चिस्टी, ललित सत्यवाना, राजेश ईशानी, गजेन्द्र रत्नवाल अतुल अग्रवाल, सुमित्रा पाठक, जगत चौधरी, श्रवण टोनी, अशोक मटाई, जितेंद्र खेवतव अजय टोगैर सहित कई जने उपस्थित थे।



सांवलिया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित किया।

‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी’

नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे रिपोर्ट जारी कर 2024 के आम चुनावों की राजनैतिक “थीम” निर्धारित की

श्रीनंद झा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर।
विधानसभा चुनावों से पहले जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी भूमिका तैयार कर ली है।
सर्वेक्षण में ओ.बी.सी. और ई.बी.सी. की अनुमानित जनसंख्या 63 प्रतिशत है जो भाजपा के हिन्दुत्व अभियान पर भारी पड़ सकती है क्योंकि अन्य राज्यों से भी जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। कांग्रेस नीत कर्नाटक सरकार पूर्व की सिद्धार्थ सरकार द्वारा कर्वाई गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है।

कास्ट सर्वे रिपोर्ट में ओ.बी.सी. व ई.बी.सी. (इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास) की आबादी को 63 प्रतिशत बताया गया है। विपक्ष का मत है कि, यह कदम भाजपा के हिन्दुत्व पर भारी पड़ सकता है।
अब यह मांग उठने की संभावना है कि, जनसंख्या के आधार पर ओ.बी.सी. का आरक्षण कोटा 27 प्रतिशत से बढ़ाया जाए।

तमिलनाडू सहित कम से कम पांच राज्य सरकारी नौकरियों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशांतरगत आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को लॉच चुके हैं। बिहार का सर्वेक्षण जारी होने के बाद यह मांग उठेगी कि ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाय।

राहुल गांधी की पार्टी की पूर्व की धारणा से अलग हटकर ओ.बी.सी. के लिए जातीय जनगणना की मजबूत वकालत कर रहे हैं। इससे कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है।
पटना में जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद अलग-अलग जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट जारी हो सकती है। इसमें सरकारी नौकरियों में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व, उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति जैसे मानदंड हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में तो जोर शोर से यह मांग उठ रही है, “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी।” बिहार के वरिष्ठ प्रेक्षक ने कहा कि आगामी माहों में यह मांग पूरे देश में आग की तरह फैलेगी।

नांदेड के सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत

नांदेड, 2 अक्टूबर। महाराष्ट्र में नांदेड के शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित रूप से दवाओं की कमी के कारण पिछले 24 घंटों में कम से कम

बताया जाता है कि, शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल में दवाओं की भारी कमी से यह हादसा हुआ है, मृतकों में 12 नवजात बच्चे भी हैं।

24 गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मौत हो गयी। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि, मृतकों में 12 नवजात शिशु भी शामिल हैं। बताया जाता है कि, राज्य भर के सरकारी अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई करने वाली कंपनी हाफकिन इन्स्ट्र्यूट ने दवाइयों की खरीदारी बंद कर दी है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं’

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के लिए गठित कमेटी के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, अभी एक ही बैठक हुई है सभी की राय ली जाएगी। इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी नहीं है।

श्रीनगर, 2 अक्टूबर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि, देश में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं है।
आजाद पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने के लिए सरकार की “एक राष्ट्र एक चुनाव” अवधारणा की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले महीने अपनी पहली आधिकारिक बैठक की।
उन्होंने कहा कि, समिति की केवल प्रारंभिक बैठक हुई थी और यह एक परिचयात्मक बैठक थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे लागू करने में कोई जल्दबाजी है, जैसा कि कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं। राष्ट्रीय दलों,

हिमाचल के लाहौल में हिमपात

शिमला, 2 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। शिमला में बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले गिरे हैं। लाहौल-स्पीति व कुल्लू में हल्की बर्फबारी और बारिश हुई। मनाली में सुबह बारिश हुई।

मनाली-लेहमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, हालांकि देर शाम सीमा सड़क संगठन ने रास्ता खोल दिया।

मनाली-लेह मार्ग पर वाहन आवाजाही को बर्फबारी के कारण विंगजिंगबार से आगे रोक दिया गया है। बारालाचा दर्रे में बर्फ जमने से दारचा से आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
देर शाम तक सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया, लेकिन यातायात आवाजाही पर प्रशासन फैसला लेगा। दो से तीन दिनों में मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा। छह जिलों, कांगडा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में मानसून सीजन खतम हो चुका है, जबकि जिला शिमला के निचले भागों से यह आंशिक रूप से जा चुका है। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, मंडी और शिमला के उपरी क्षेत्रों से यह मानसून दो-तीन दिनों के भीतर विदा हो जाएगा। पिछले वर्ष भी 3 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था।

कर्नाटक में कांग्रेस भी जातिगत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जुबानी जमा खर्च कर रही है लेकिन सबसे पिछड़े वर्ग के हितों की पूर्णतया अनदेखी कर रही है। राहुल ने कहा कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ओ.बी.सी. से होना समाज के वंचित वर्ग के प्रति अन्याय है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक जातीय जनगणना हकर हर जात की संख्या सामने नहीं आती। तब तक उनके लक्षित लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने वादा किया कि अगर केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले जातीय जनगणना होगी।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मौके पर उठाए गए इस मुद्दे ने भाजपा को परेशान कर दिया है जिसकी पूर्व में पुनियोजित सोशल इंजीनियरिंग ने उसे देश भर में ओ.बी.सी. का भारत समर्थन दिलाया था जिससे उसे भारी बहुमत मिला।
कर्नाटक में कांग्रेस के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि राज्य सरकार शीघ्र जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी कर रही है। पिछली सिद्धार्थ सरकार (2013-

2018) में जातीय जनगणना हुई अवश्य थी लेकिन कार्यकाल समाप्त होने तक जारी नहीं हो पाई।
हालांकि रिपोर्ट जारी करने में एक संशय यह है कि जातीय जनगणना के आंकड़े दो जातियों का प्रभुत्व कम कर सकते हैं-लिंगायत और वोक्कालिंगा, क्योंकि असली आंकड़े इस धारणा को चुनौती दे सकते हैं कि राज्य की आबादी में उनका बड़ा हिस्सा है।
यह संशय अवश्य है कि, जातीय जनगणना के आंकड़ों से कुछ और आंतरिक विभाजन हो सकते हैं। जिससे आरक्षित सीटों में फेरबदल हो सकता है। अभी कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 36 आरक्षित हैं।
जनगणना के आंकड़े जारी करने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार एकमत हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ओ.बी.सी. का मुद्दा इतनी मजबूती से उठा रहा है कि कर्नाटक राज्य सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करेगी।
लेकिन इससे यह तथ्य समाप्त नहीं हो जाता कि इसमें कई स्थानीय मुद्दे भी हैं जिससे जातीय आंकड़ों से राजनैतिक गठबंधन और सामाजिक

शक्तियों का समीकरण विगड़ सकता है। कुशल आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण और जातीय जनगणना के पक्ष में यह तर्क है कि इससे सरकार असमानताओं को कम कर सकेगी और ओ.बी.सी., दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को राजनीति, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व दे सकेगी।

राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पहुंचने पर राणा के. पी. सिंह, सांसद गुरुजीत सिंह औजला, इंटक नेता सुरिंदर शर्मा तथा अन्य नेताओं स्वागत किया। स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। गांधी का अन्य धार्मिक स्थलों पर भी मत्था टेकने का कार्यक्रम है।
उन्के इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़गाँव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि, गांधी स्वर्ण साहिब में मत्था टेकने के लिए अमृतसर आ रहे हैं। यह उनकी निजी और आध्यात्मिक यात्रा है, उनकी निजता का सम्मान करते। सभी

सांवलिया जी में मोदी की विशाल सभा, 50,000 लोग आए

प्र.मंत्री मोदी ने कहा चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, कमल का फूल

उदयपुर/मंडफिया, 2 अक्टूबर (कांस)। प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने से पहले भाजपा पूरी तैयारी में जुट गई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलियाजी मंदिर में पूजा-अर्चना कर भारी जनसभा को संबोधित किया, तथा सांवलिया जी में 7000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने इस बार चुनाव में “कमल के फूल” को भाजपा का चेहरा बताया, वहीं कांग्रेस की गहलोल सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। सभा में करीब 50 हजार की भीड़ जुटी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे जहां से वे हेलीकॉप्टर द्वारा चित्तौड़गढ़ रवाना हो गए।
पीएम मोदी ने सांवलिया जी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके पास अतीत की विरासत है, वर्तमान की ताकत है और भविष्य की संभावनाएं हैं। नाथद्वारा पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि, यह पर्यटन सर्किट का हिस्सा है, जिसमें

- मोदी ने कमल के फूल को चेहरा बता कर एक बार फिर साफ कर दिया कि, पार्टी यहां किसी को भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। इसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए झटका बताया जा रहा है।
- मोदी ने सांवलिया जी में 7000 करोड़ रु. की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- मोदी ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री गहलोल पर कटाक्ष किए और कहा, गहलोल तो पूरे समय कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी से ज्यादा कांग्रेस उन्हें कुर्सी से गिराने की कोशिश करती रही।

जयपुर का गोविंद देव मंदिर, सोकर का खाद श्याम मंदिर और राजसमंद का नाथद्वारा शामिल है। इससे राजस्थान का गौरव बढ़ेगा व पर्यटन उद्योग को लाभ होगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत सांवलिया सेठ मंदिर में विकास होने से तीर्थयात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, राजस्थान का इतिहास हमें सिखाता है कि, हमें वीरता, गौरव और विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज भारत इसी परिपाटी पर चल रहा है। मोदी ने कहा, आगामी चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और

वह चेहरा है “कमल का फूल” और इस कमल के नेतृत्व में ही राजस्थान का भाग्य तेज गति से आगे बढ़ाएगा। मोदी ने कहा कि हमारी उम्मीद व उम्मीदवार कमल ही है। भाजपा को जिताने, इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एकजुट होकर ताकत के साथ निकलना होगा। कहा जा रहा है कि, कमल को पार्टी का चेहरा बताने के साथ ही मोदी ने यहां पर सपने संजोएं बैठी वसुंधरा को दरकिनार करने का संदेश दिया है।
मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए

कहा, मैं दुखी मन से कह रहा हूँ कि, आज जब अपराध की बात आती है तो राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाए। यहां गहलोलतु जी उठते-बैठते, सोते-जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे, वहीं आधी से अधिक कांग्रेस उन्हें गिराने में जुटी थी। वे जनता को अपने हाल पर छोड़ आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी में लगभग 7000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में मेहसाणा-भटिंडा-गुरदासपुर गैस पाइपलाइन, आबू रोड में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का एलपीजी संयंत्र, अजमेर बॉटलिंग प्लांट में अतिरिक्त पंढारण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) रेलवे और सड़क परियोजनाएं, नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाएं और कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मशीनी परिसर शामिल हैं।

नवरात्रि में घोषित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
यादव बालकनाथ शामिल है। राजस्थान में दो केन्द्रीय मंत्रियों अर्जुनराम मेघवाल और गजेन्द्र सिंह शेखावत को भी मैदान में उतारा जा सकता है और अटकलें हैं कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है।
पार्टी छत्तीसगढ़ में 21 नामों की घोषणा कर चुकी है और दूसरी सूची शीघ्र जारी कर सकती है। पहले नेतृत्व वसुंधरा राजे की जगह चार बार सांसद रहे उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को खड़ा करने की सोच रही थी लेकिन अब उसकी संभावना नहीं है क्योंकि पार्टी परिवार में से एक को ही टिकट देगी। पार्टी के सूत्रों ने कहा उम्मीदवारों की सूची जमीनी रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के आधार पर बनाई गई है।

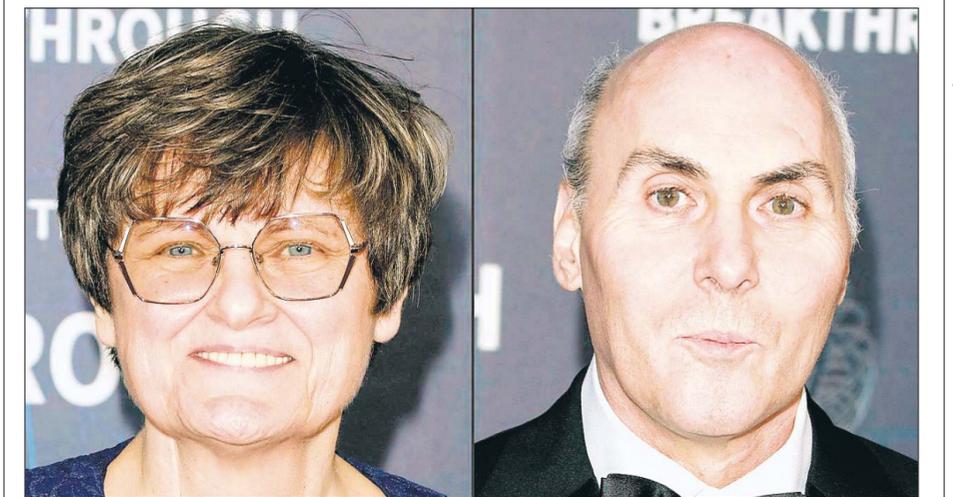
दिल्ली का 3 लाख रु. का इनामी आतंकी गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजधानी में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड करते हुए आई.एस.आई.एस. मॉड्यूल के एक मोस्ट वांटेड आतंकीवर्ग सहित अन्य तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि, गिरफ्तार आतंकीवर्ग का नाम मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा है। पुलिस ने शाहनवाज से पूछताछ के बाद तीन

बताया जाता है कि मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा के सम्बन्ध आई.एस. से हैं और वह किसी बड़ी वारदात करने की तैयारी में था।

अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। शाहनवाज पर तीन लाख रुपये का इनाम था। बताया जा रहा है कि, शाहनवाज

और एक अन्य को जहां दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, वहीं तीसरे संदिग्ध को दिल्ली के बाहर से दबोचा गया है। ये आतंकी मॉड्यूल उत्तर भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहनवाज पेशे से इंजीनियर है और राष्ट्रीय राजधानी का रहने वाला है। कुछ समय पहले पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था और तब से वह दिल्ली में ही रह रहा था।



चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। शरीर-क्रिया विज्ञान एवं औषधि (फिजिऑलॉजी एवं मेडिसिन) क्षेत्र के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी मूल की जैव-रसायन वैज्ञानिक कैटलिन कारीको और अमेरिका के डू वाइजमैन को एम-आरएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से देने की सोमवार को घोषणा की गयी। नोबेल असेंबली के सचिव थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम के कारोलींस्का संस्थान में इस पुरस्कार की घोषणा की। दोनों वैज्ञानिकों को न्यूक्लियोसाइड आधारित संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के सम्मान के तौर पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बयान के अनुसार उनकी खोज से कोरोना वायरस-कोविड-19 से बचाव के लिए एम-आरएनए टीकों के विकास में मदद मिली। कैटलिन कारीको मूल रूप से हंगरी की हैं और अमेरिका में बस गयी हैं। वे बायोकेमिस्ट हैं और उन्हें आरएनए के हस्तक्षेप से प्रभावित शारीरिक क्रियाओं की व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। कैटलिन ने प्रोटीन उपचार के लिए इन विट्रो-ट्रांसक्राइब एम-आरएनए के विकास पर शोध किया है। वे पैन्सिल्वनिया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक वाइजमैन ने पैन्सिल्वनिया विश्वविद्यालय में ही कारीको के साथ मिल कर शरीर के अंदर न्यूक्लियोसाइड आधारित परिवर्तन पर अनुसंधान किया।

बिहार कास्ट सर्वे: भाजपा नेतृत्व...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा ने सर्वे का दृढ़ता से समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि “भाजपा ने सर्वे का पूर्ण समर्थन किया था। हम जब बिहार में सरकार का हिस्सा थे, तब हमने ही यह कार्य शुरू किया था।”
प्रकाशित डेटा से पता चला है कि बिहार की कुल आबादी में ओ.बी.सी. और ई.बी.सी. को 63 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा है। विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा पटना में जारी किए गए डेटा के अनुसार राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ से थोड़ी ही अधिक है और उसमें से एकसठतीसवां बैकवर्ड क्लासेस (ई.बी.सी.) 36 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है व उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस (ओ.बी.सी.) 27.13 प्रतिशत है।
सर्वे में यह भी बताया गया कि ओ.बी.सी. में आने वाले यादव, जिन्से उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी ताल्लुक है, वह कुल आबादी के 14.27 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा

ओ.बी.सी. ग्रुप है।
दलित, जिन्हें अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाता है, राज्य की कुल आबादी का 19.65 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आबादी 22 लाख यानी कि 1.68 प्रतिशत है।
अनारक्षित वर्गयानी कि सर्वविदित “सर्वर” जिनका 1990 के दशक की मण्डल लहर तक राजनीति में दबदबा था की जनसंख्या कुल आबादी का 15.52 प्रतिशत है।
सर्वे में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि राज्य की कुल आबादी में हिन्दुओं की संख्या 81.99 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम 17.7 प्रतिशत है।
अन्य धर्मों को मानने वाले ईसाई, सिख, जैन और अनौषधवादीयों की आबादी की भी राज्य में नाम मात्र की उपस्थिति है। इन सभी की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या के एक प्रतिशत से भी कम है।
“इण्डिया” गठबंधन के गठन में प्रसाद और कुमार दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस गठबंधन ही हाल ही बैंगलुरु में हुई मीटिंग में जातिगत जनगणना की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई

थी और उस प्रतिबद्धता को अब पूरा कर लिया गया है।
केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जब यह स्पष्ट कर दिया था कि वह जनगणना में एस.सी. और एस.टी. के अलावा अन्य जातियों के लोगों की गणना में समर्थ नहीं होगी, उसके बाद ही इस प्रकार का सर्वे कराने के पिछले वर्ष आदेश दिए गए थे।
इससे पहले सभी जातियों के लोगों की गणना वर्ष 1931 में की गई थी। जो लोग जातियों का नवीनतम सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं उनका यह जोर देकर

कहना है कि स्वतंत्रता के बाद के युग में बेहतर जीवन प्रत्याशा वाले समाज के जिन कमजोर वर्गों की आबादी में अनुपातिक वृद्धि हुई है, उनके लिए एक नया आकलन बेहद जरूरी है।
राज्य मंत्रिमण्डल ने गत वर्ष 2 जून को एक जातिगत सर्वे का अनुमोदन किया था और इसके लिए 5 सौ करोड़ रुपये की भारी भरकर राशि स्वीकृत की गई थी। सर्वे के काम में हल्का सा रोड़ा तब अटक गया था जब इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहे पटना हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी।

डिजाइन बॉक्स...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रहे हैं, मुख्यमंत्री के अलावा किसी के साथ भी को-आपरेट करने से इन्कार कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो कि राज्य में संगठन के प्रभारी भी हैं, के साथ अपनी प्रचार योजनाओं को शेयर करने से भी इन्कार कर रहे हैं। अब यह देखा मजेदार होगा कि अशोक गहलोल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या डिजाइन बॉक्स को अथी भी मुख्यमंत्री गहलोल का वरदहस्त प्राप्त होता रहेगा।

सीटों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अन्य पार्टियों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, लेकिन इसे लेकर कई पार्टियों के बीच मतभेद हैं। भोपाल रेली के रहने वाले बंधु हैं पांच संयुक्त रैलियों में भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे संकेत हैं कि सीट शेयरिंग के निर्णय के लिए पार्टियों को नवम्बर माह में होने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों तक इन्तजार करना होगा।